● वर्ष-4
● अंक-138
रायपुर, रविवार
19 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» तुलसी की खेती

पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे।

इसमें 12 राज्यों के 50,000 से ज्यादा गांव शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। पीएम मोदी वर्चुअल मोड में इस इवेंट में शामिल हुए। जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। जिन 12 राज्यों में यह कार्ड बांटे गए, उनमें से 230 जिलों के 50 हजार से ज्यादा गांव शामिल हैं। अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का संपत्ति कार्ड तैयार किया जा चुका है।

लाभार्थियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन देश के गांवों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांवों में रहने वालों का उनका कानूनी प्रमाण दिया जा सके। बीते 5 साल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्लाइमेंट चेंज संबंधी चुनौतियों का भी जिक्र किया। बोले, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी.. ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बड़ी चुनौती रही है और ये चुनौती है- प्रॉपर्टी राइट्स की।कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक-अनेक देशों में भू-संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है।

बता दें, स्वामित्व योजना अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी। जिसका पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाना है। अब तक 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी पूरी

भूमिहीन श्रमिकों को 10-10 हजार सालाना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी जी की एक और गारण्टी को पूरी करने की घोषणा की है। राज्य के ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रूपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में आज ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 5 लाख 62 हजार श्रमिकों को फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सक्ती जिले के दमऊदरहा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज लगभग 170 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से सक्ती जिले के विकास को नई गति मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह बंधन में बंधे 15 जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह शुभ अवसर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का भी है। 144 साल बाद यह

शुभ संयोग बना है। सनातन धर्म की इस महान परंपरा का पुण्य लाभ लेने का यह अच्छा अवसर है। हमारे छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्री भी इसका लाभ उठायें, इसके लिए हमारी सरकार ने मेलास्थल में साढ़े चार एकड़ क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की है। हमारे प्रदेश से जो श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, वहां उनके लिए ठहरने और भोजन का भी इंतजाम है। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ पैवेलियन में हमने अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को विशिष्ट रूप से दिखाया है जो लोगों को काफी भा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी। इनमें से कई हितग्राही अपने आवास में गृह प्रवेश कर रहे है। बीते दिनों केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग के नगपुरा आए थे जहां उन्होंने 3.5 लाख अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी है, वे भी आवास हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जिन विकास कार्यों की राह देख रही थी, उसे हम आज पूरी तेजी से पूरा करने का काम कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता के कामों में लग रहा है। सक्ती जिले में 6 नगरीय निकायों के लिए बीते एक साल में 77 करोड़ रुपए दिए गए। 31 सौ रूपये में धान खरीदी हो रही, महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है, आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है, इससे ग्रामीण विकास को नई रफ्तार मिली है। कार्यक्रम को सांसद मती कमलेश जांगड़े ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक रामकुमार यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

डॉ. रमन मिले गृहमंत्री से

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह ने आज अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की. इस अवसर पर डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को माडिया मदिन युगल नृत्य की प्रतिमा भेंट की.इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. इनमें राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।

डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राज्य में किए जा रहे विकासात्मक प्रयासों की जानकारी भी दी.

दिल्ली में नहीं लागू होगी आयुष्मान भारत योजना

एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नईदिल्ली। महिलाओं के शारीरिक ढांचे पर टिप्पणी को केरल हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न बताया। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना। कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा कि हम हलफनामा देखकर हैरान हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में 162 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया। इस सप्ताह यानी 13 जनवरी से 18 जनवरी 2025 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें आप सरकार को आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी को फिर से परिभाषित किया है। सिंघवी ने शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होते हुए कहा वे हमें मजबूर नहीं कर सकते। हाई कोर्ट मुझे नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन का विरोध करते हुए कहा है कि यह पहले से मौजूद स्वास्थ्य देखभाल पहलों को कमतर करने जैसा होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की वेंच ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने संबंधी सेंगर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

प्रमुख समाचार

पटना में आंदोलन कर रहे छात्रों से मिले राहुल गांधी

नईदिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के पटना के गर्दनीबाग धरनास्थल पर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के

खिलाफ बल प्रयोग कर रही है और दावा किया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने गरीब मेहनती छात्रों के सपनों को कुचल दिया है। राहुल ने लिखा कि पटना में गर्दनीबाग धरनास्थल जाकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाक़ात की। उन्होंने बताया कि किस तरह बीपीएससी अन्याय कर रही है और बिहार सरकार लाठी डंडे की चोट दे रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन वाली सरकार है। लेकिन फेल हो चुके इस इंजन से ग़रीब मेहनती छात्रों के सपनों को कुचला जा रहा है - युवा शक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी नौकरी की कोई भी भर्ती इनसे बिना पेपर लीक या धांधली के पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि छात्रों ने बताया कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए।

मोदी के नेतृत्व में भारत पहले स्थान पर होगा : नायडू

अमरावती । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के विकास के लिए ''डबल इंजन'' सरकार को आवश्यक बताते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में देश 2047 तक

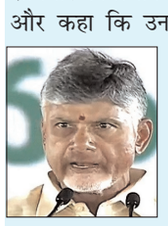

दुनिया की नंबर एक या दो अर्थव्यवस्था बन सकता है। नायडू ने कडप्पा जिले के म्यदुकुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)द्वारा जीती गई कुल 25 लोकसभा सीटों में से 21 सीट 'संजीवनी' की तरह हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ''आर्थिक रूप से वेंटिलेटर पर है'' और केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति की जा रही ऑक्सीजन पर जीवित है।तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो नायडू ने कहा कि उनका दल एक करोड़ सदस्यों वाला एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन इसने हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ काम किया है। उन्होंने कहा, ''हमने 2014 से 2019 के बीच राजग के साथ काम किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक दुनिया में पहला या दूसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

कर्नाटक में गरीबों के लिए 4.68 लाख मकान मंजूरः शिवराज

बेंगलुरु । केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त 4.68 लाख मकानों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण विभाग का प्रभार संभाल रहे चौहान ने यहां

संवाददाताओं को बताया कि यह केंद्र द्वारा मूल रूप से स्वीकृत 2.57 लाख मकानों के अलावा है। मंत्री ने कहा कि आज सुबह उनकी कर्नाटक के ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक हुई। नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत सितम्बर में 2.57 लाख मकान स्वीकृत किये तथा इसके लिए अनुदान भी जारी किया। मंत्री ने कहा, अब हमने लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है और कुल मिलाकर 4.68 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। भाजपा के लिए गरीबों की सेवा करना भगवान की पूजा है। चौहान ने कर्नाटक सरकार से आवास परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत कर्नाटक के लिए 97 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया सैफ पर हमला करने वाला संदिग्ध

दुर्ग। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके आवास पर हुए हमले के सिलसिले में शनिवार को छत्तीसगढ़ में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। मुंबई पुलिस की एक टीम संदिग्ध से पूछताछ के लिए दुर्ग जा रही है। संदिग्ध की

पहचान 31 वर्षीय आकाश कैलाश कन्नोजिया के रूप में हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने तब रोका जब वह दुर्ग जिले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ रहा था। मुंबई पुलिस ने संदिग्ध की फोटो और लोकेशन की जानकारी देकर रेलवे पुलिस को अलर्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ आरपीएफ के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान हमले के आरोपी की जो फोटो शेयर की है, उसकी शक्ल ट्रेन से हिरासत में लिए गए शख्स से मिलती है। हमें मुंबई पुलिस से जानकारी मिली कि एक संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा है।उन्होंने उसकी फोटो और टावर लोकेशन शेयर की. उस आधार पर हमने ट्रेन के एक जनरल कोच की जांच की और उसे ढूंढ लिया. वीडियो कॉल के जरिए मुंबई पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया गया और संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की गई।

राजस्थान में महिला शिक्षा का गला घोंट रही भाजपाः गहलोत

जयपुर । राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार महिला शिक्षा का गला घोंट रही है। गहलोत ने सरकार द्वारा बालिका विद्यालयों को बंद किए जाने संबंधी एक खबर साझा करते हुए

'एक्स' पर कहा, कालीबाई भील की धरती राजस्थान में महिला शिक्षा का गला घोंट रही है भाजपा। कांग्रेस नेता ने कहा, अच्छी नामांकन संख्या वाले विद्यालयों को बंद करना भाजपा की महिला शिक्षा पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' है। इनका छिपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है, ये नहीं चाहते कि लड़कियां पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर को कम से कम करने के लिए कम नामांकन होने पर भी विद्यालयों को सक्रिय रखा ताकि एक भी बच्ची को पढ़ाई न छोड़नी पड़े। हमने नीति बनाई कि जिन विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षा में बालिकाओं का नामांकन 500 से अधिक होगा, वहां कॉलेज खोल दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, भाजपा की अदूरदर्शी नीतियां राजस्थान को पीछे धकेल रही हैं, जिसका खामियाजा उन बच्चियों को भुगतना पड़ रहा है।

मेटा की माफी से सोशल मीडिया मंचों को सख्त सन्देश

ललित गर्ग

फेसबुक के लिये भारत एक संभावनाओं भरा बड़ा बाजार होने के बावजूद उसकी भारत के प्रति सोच भ्रामक, विवादास्पद एवं नकारात्मक रही है। फेसबुक और मेटा भारत के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और फेकन्यूज को लेकर विवादों में घिरती रही हैं। हाल ही में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग एक बार फिर भारत को लेकर दिये गलत बयान के मामले में फंस गए हैं। जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मौजूदा सरकारें गिर गईं। भारत के लोकसभा चुनाव में भी नरेन्द्र मोदी सरकार हार गई। यह जनता का सरकारों में घटता भरोसा दिखाता है। इस बयान के बाद संसद की आईटी एंड कम्युनिकेशन मामलों की स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि इस गलत बयान पर कंपनी को माफी मांगनी चाहिए। वरना हमारी समिति उन्हें मानहानि का नोटिस भेजेगी। भारत सरकार की सख्त आपत्ति को देखते हुए भले ही मेटा ने माफी मांग ली हो, लेकिन मार्क भरोसे के लायक नहीं है। यह माफी जहां जरूरी थी वही अब स्वागतयोग्य भी है। लेकिन मार्क का भारत के प्रति नजरिया गैर जिम्मेदाराना, लापरवाहीपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। ऐसी निरंकुश सोच एवं उच्छृंखल मानसिकता की बुनियाद पर संबंधों की खड़ी होने वाली इमारत खोखली एवं विनाशकारी ही होती है।

यह वाकई हैरत की बात है कि जुकरबर्ग ने भारत को भी उन देशों में शामिल कर लिया जहां पिछले साल चुनाव में सरकारों ने सत्ता गंवाई। तथ्य यह है कि भाजपा की सीटें भले कम हुई हों, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने बहुमत हासिल कर सरकार में वापसी की एवं सफलतापूर्वक सरकार को चला रही है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और न केवल देश में बल्कि दुनिया में भारत का परचम फहरा रहे है। इस तथ्य से जकरबर्ग कैसे अनजान हो सकते हैं? क्या वह जानबूझकर भारत सरकार के बारे में गलत सूचनाएं फैला रहे हैं? क्या यह शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्रों के साथ-साथ वहां की बड़ी आर्थिक शक्तियों की भारत के प्रति विरोधाभासी दुर्भावना नहीं है। कैसे मान लिया जाये कि यह गलती अनजाने में हुई है?

मेटा इंडिया भी जुकरबर्ग की ही कंपनी है, जिसके एक आला अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह मेटा के लिए भारत

एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण एवं संभावनाभरा खास देश बना हुआ है। मेटा अपने व्यापार को भारत में विस्तारित करने के लिये विभिन्न योजनाओं पर काम भी कर रहा है। भारत मेटा के लिए बहुत अहम देश है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कैंपस में भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2024 में जामनगर में हुए बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन में जुकरबर्ग शामिल हुए थे। तभी उन्होंने रिलायंस के साथ इसको लेकर एक समझौता किया था। इस तरह मेटा के लिए भारत अहम है, तो इसके मालिक को भारत का नाम बहुत संभलकर एवं सोच समझकर लेना चाहिए। वैसे भी भारत सरकार अमेरिका, यूरोपीय देशों या चीन की तरह आक्रामक एवं उग्र नहीं है। आक्रामक देशों में तो सरकारें फेसबुक या मेटा की गलतियों पर उसे न केवल सबक सीखाती है बल्कि कई बार ऐसी गलतियों के चलते कंपनियों को भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। उन देशों की कड़ाई का ही नतीजा है कि सोशल मीडिया कंपनियां इन देशों में बहुत सजग रहती हैं, जबकि भारत के मामले में उनकी नीति बदल जाती है। भारत की उदारता का ये कंपनियां अधिकतम दुरुपयोग करना चाहती हैं। भारत को भी उदारता, सरलता एवं लचीलेपन की जगह कठोर एवं सख्त रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने के साथ दुनिया में अपनी एक स्वतंत्र एवं ठोस जगह बना चुका है। जुकरबर्ग से जुड़ा यह ताजा मामला ऐसे ही लोगों के लिये एक सबक एवं चेतावनी बनना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को चेतावनी के शब्दों में सचेत कर दे कि वे भारत के महत्व को समझें, पर्याप्त सजग एवं सावधान रहें। भारतीयों को पता है कि साल 2019 में अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए फेसबुक पर पांच अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था।

ताजा विवाद को सरकार ने गंभीरता से लिया है, यह अच्छी बात है। लेकिन जरूरी है कि चिंता इसी मामले तक सीमित न रहे। हेट स्पीच, तथ्यों को तरोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करना और फेक न्यूज के ऐसे अन्य मामले भी राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिये गंभीर एवं चुनौतीपूर्ण है। सरकार की सख्ती जहां मेटा को ज्यादा जिम्मेदार बनाये वहीं अन्य मंचों के लिये भी सबक बने।

माफी के बाद जुकरबर्ग जैसे मालिकों को भी यह सुनिश्चित होगा कि उनके अधीन चलने वाले सोशल मीडिया मंचों पर भारत के प्रति किसी झूठ, भ्रम एवं असत्य बयानी का सिक्का न चले। क्योंकि भारत की उदारता को उसकी कमजोरी मानने की मानसिकता घातक हो सकती है।

हमास आतंकियों की तरह नक्सलियों ने सुरंग में बनाया था ठिकाना, मिली हथियारों की फैक्ट्री

रायपुर/बीजापुर। दो दिन (16 और 17 जनवरी) तक चले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान जवानों की ओर से बनाया गया एक वीडियो सामने आया है, जो इस नक्सल अभियान की सच्चाई और नक्सलियों के नापाक मंसूबों को उजागर करता है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में पहली बार फिलिस्तीन के हमास आतंकियों की तरह सुरंग में हथियारों की फैक्ट्री मिली है।

बताया जाता है कि इस बारुदी सुरंग को दो करोड़ के इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा ने बनवाया था। नक्सलियों ने हमास आतंकवादियों की तरह छुपने के लिये सुरंगों में ठिकाना बनाया हुआ था। बड़ी लेथ मशीनों के जरिये नक्सली बंदूकें, देसी रॉकेट और राकेट लॉन्चर बना रहे थे। सुरंगों में हथियार बनाने की फैक्टरी लगा रखी थी। नक्सलियों की इसी सुरंग में देसी रॉकेट और रॉकेट लांचर बनाये जाते थे।

दूसरी ओर दुर्दांत नक्सली हिड़मा की बटालियन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) और सेंट्र्ल रीजनल कमेटी (सीआरसी) से ज्वॉइट फोर्स की जब मुठभेड़ चल रही थी। इस दौरान जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली हिड़मा और देवा पहाड़ी

की तरफ भाग घने जंगलों की ओर जान बचाकर भाग निकले। माना जा रहा है कि वह सुकमा के बीहड़ क्षेत्रों में या तेलंगाना की सीमा में छुपा बैठा है। यदि वह फोर्स के इस खास नक्सल ऑपरेशन से नहीं बच पाता, तो उसका एनकाउंटर तय था।

हिड़मा के बटालियन पीएलजीए की कमर टूटी

ऐसे में माना जा रहा है कि खूंखार नक्सली हिड़मा के बटालियन पीएलजीए की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। इस बड़े नक्सल ऑपरेशन में तीन जिलों के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), सीआरपीएफ की विशिष्ट जंगल युद्ध इकाई कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन) की पांच बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229वीं बटालियन के जवान शामिल थे।

बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर व मारुड़बाका के जंगल में गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया था, जिनके शव भी बरामद कर लिये गये हैं। जवानों ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। गुरुवार को सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दक्षिण बीजापुर के जंगल में देर रात से सुबह तक रुक-रुक कर मुठभेड़ होती रही। नक्सली बड़ी बैठक ले रहे थे। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कैडर के हार्ड कोर नक्सली बैठक में शामिल थे।

सुरंग में मिला नक्सलियों का जखीरा

सुरक्षाबलों को तलाशी में सुरंग में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। पता चला है कि नक्सली लेथ मशीन की मदद से हथियार बनाते थे। बड़ी संख्या में पाइप, बिजली के तार और अन्य सामग्री मिली है। जवानों ने सुरंग को पाट दिया है।

हिड़मा ने जवानों पर फायरिंग कराने के लिए नाली को जेसीबी की मदद से बनवाया था। फोर्स से छुपाने के लिए सुरंगों को लोहे की मोटी प्लेट से ढक रखा था ताकि गोली अंदर न जा सके और नक्सली सुरक्षित रह सकें। इस सुरंग की लंबाई 12 से 15 फीट और उंचाई करीब 8 फीट बताई जा रही है। बताया जाता है कि जो लोहे की पाइप, बिजली के तार, लोहे की मोटी प्लेट और लेथ मशीन आदि नक्सलियों ने लूटे हुए सामान हैं। चर्चा ये है कि ये सारे सामान नक्सलियों के शहरी नेटवर्क की ओर से उन्हें उपलब्ध कराई जाती है।

कौन है खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा?

बस्तर में नक्सल आतंक का पर्याय बन चुके खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा को संतोष उर्फ इंदमुल उर्फ पोडियाम भीमा जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है। सुकमा उसका गढ़ माना जाता है। यहां पर होने वाली सभी नक्सल गतिविधियों पर उसका नियंत्रण रहता है। वह वर्ष 1990 में नक्सलियों के संगठन से जुड़ा। पिछले कई साल से सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी है। छत्तीसगढ़ में कई नक्सली हमलों को अंजाम देने वाले इस दुर्दांत नक्सली का जन्म सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में हुआ था। यह गांव दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि इस गांव में पहुंचना मुश्किल है। इसके बाद भी फोर्स के हौसले को सलाम है, जो कठिन डगर के बावजूद उसके गढ़ में पहुंच चुकी है।

कई बड़े नक्सली हमले का है मास्टरमाइंड

कद-काठी में छोटे से दिखने वाले हिडमा का नक्सली संगठन में बड़ा नाम है। बताया जाता है कि उसके नेतृत्व काबिलियत के बल पर ही उसे 13 साल की उम्र में नक्सलियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया। उसकी परवरिश उस समय हुई जब सुकमा में नक्सली घटनायें चरम पर थीं। बताते हैं कि हिडमा केवल दसवीं तक पढ़ा है। बताया जाता है कि वह अपने साथ हमेशा एक नोटबुक लेकर चलता है, जिसमें वह अपने नोट्स लिखता रहता है।

साल 2010 में ताड़मेटला में हुए हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत में हिड़मा का नाम सामने आया था। इसके बाद साल 2013 में हुए झीरम हमले में भी हिडमा की भूमिका थी। इस हमले में कई बड़े कांग्रेसी नेताओं सहित 31 लोग दिवंगत हो गये थे। साल 2017 में बुरकापाल में हुए हमले में भी हिडमा की अहम भूमिका थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहादत को प्राप्त हुए थे। बताते हैं कि हिडमा ने फिलीपींस में गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली है।

जानें क्या है पीएलजीए

पीएलजीए प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की सशस्त्र ब्रांच है। पीएलजीए बटालियन नंबर एक को नक्सलियों का सबसे मजबूत बल माना जाता है। इसका नेतृत्व खुद हिड़मा कर रहा है। इस नक्सली ने बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में कई बड़े नक्सली हमले किये हैं। बस्तर संभाग में कुल सात जिले आते हैं जहां पर नक्सलियों का यह संगठन काफी मजबूत है।

नई पुनर्वास नीति का असर

10 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया सरेण्डर

कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन की ''नई नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति'' और जिले में चलाये जा रहे नक्सल अभियान के कारण नक्सलियों के हिंसक और शोषणकारी विचारधारा से तंग आकर कई माओवादी विकासशील समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के साथ साथ कबीरधाम जिले में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आज इसी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 10 लाख ईनामी नक्सली दंपत्ति रमेश और रोशनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, जो कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूवर्ती निवासी हैं। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का ईनाम रखा गया था।

जानकारी के मुताबिक, रमेश उर्फ मेस्सा बोड़ला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 का डिप्टी कमांडर था। वहीं उसकी पत्नी रोशनी उर्फ हिड़में भी बोड़ला एरिया कमेटी विस्तार प्लाटून नंबर 3 की सदस्य थी। दोनों ने आज कबीरधाम पुलिस के पास जाकर सरेण्डर किया है। इन दोनों पर थाना तरेगांव में दर्ज 2-2 नक्सल अपराध दर्ज हैं।

'रमेश उर्फ मेस्सा' ने नक्सली संगठन में डिप्टी कमांडर के रूप में काम करते हुए कई हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया था एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल रहा वह संगठन में रहने के दौरान एस एल आर राइफल धारी रहा है। वहीं, 'रोशनी उर्फ हिड़में' संगठन की प्रशिक्षित सदस्य थी, जो नक्सली हिंसा में सक्रिय भूमिका निभाती रही तथा संगठन में इन्सास राइफल धारी थी। दोनों ने संगठन में व्याप्त आंतरिक संघर्ष, अमानवीय व्यवहार, स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार, और जंगलों में जीवन की कठिनाईयों से परेशान होकर आत्मसमर्पण का निर्णय लिया।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह छवई ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति को छत्तीसगढ़ शासन की ''पुनर्वास नीति'' के तहत दोनों को पृथक-पृथक 25,000-25,000 रुपये (कुल 50,000 रुपये) की प्रोत्साहन राशि तत्काल नगद प्रदान की गई। इसके साथ ही भविष्य में 3 वर्ष तक 10,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड राशि, निःशुल्क आवास एवं भोजन, स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रशिक्षण, कृषि भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आपको बताते चले कि अब तक जिले में 8 ईनामी नक्सलियों सहित कुल 9 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और समाज की मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं।

बिलासपुर में अनारक्षित टिकट घर गेट नं 1 के पास होगा स्थानांतरित

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर स्टेशन को 392 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है ।बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के अंतर्गत स्टेशन परिसर का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है । इसके तहत बिलासपुर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को उच्च स्तरीय सेवाएँ, बेहतर यात्री सुविधाएँ और स्वच्छ व सुगम परिवेश उपलब्ध कराने विभिन्न निर्माण कार्य शामिल है । स्टेशन को पर्यावरण-अनुकूल तकनीक और डिज़ाइन से पुनर्विकसित भी किया जा रहा है।

स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पुनर्विकास के अंतर्गत यात्रियों की सुविधा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इस निर्माण कार्य के दौरान स्टेशन पर अस्थायी रूप से कुछ सेवाएं और सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

इस निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को स्टेशन आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसलिए रेल प्रशासन द्वारा अनेक प्रबंध/बदलाव किये जा रहे हैं । इसी कड़ी में गेट नं 3 के अनारक्षित टिकट घर को गेट नं 1 के पास स्थित आरक्षण टिकट घर में शीघ्र ही स्थानांतरित किया जाएगा। उपरोक्त बदलाव निर्माण कार्य के पूर्ण होने तक रहेगा । इसके साथ ही स्टेशन के प्लेटफार्म में उपलब्ध अन्य सुविधाएं यथावत रखी गई है ।

डायनेमिक इंटरप्राइजेज ने श्रमिकों को वेतन न देकर किया 26,23,776 की धोखाधड़ी

■ कोर्ट का आदेश 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज करें मामला

दुर्ग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग कोच केयर सेंटर में साफ सफाई का कार्य करने के बाद परिवादी एवं अन्य श्रमिकों को वेतन न देकर 26,23,776 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में परिवादी द्वारा परिवाद दायर किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग पुनीत राम गुरुपंच ने मोहन नगर थाना प्रभारी को आदेशित किया कि आरोपीगण एसपी मीणा, एसके सेनापति, आचार्य एवं रामनारायण साहू के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज करें। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले को जांच में लिया है।

ग्राम नवागांव तहसील धमधा निवासी परिवादी मानसिंह सिन्हा ने परिवार दायर किया था कि डायनेमिक इंटरप्राइजेज मालवीय नगर दुर्ग के पार्टनर एसपी मीणा, सीनियर डीएमई कार्यालय रेलवे रायपुर, आचार्य तत्कालीन सीडीओ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर तथा रामनारायण साहू सीडीओ कोच डिपो ऑफिसर ने मिलकर परिवादी एवं अन्य श्रमिकों के साथ 26,23,776 रुपए की धोखाधड़ी की है। डायनेमिक इंटरप्राइजेज को रेलवे से ट्रेनों में साफ सफाई की व्यवस्था का ठेका प्राप्त हुआ था, जिसका कार्यालय मालवीय नगर दुर्ग में स्थित है। डायनेमिक इंटरप्राइजेज द्वारा रेलवे से ठेका प्राप्त कर जुलाई 2018 से अपना कार्य प्रारंभकिया और एसपी मीणा ने पूर्व में कंपनी के अधीन काम करने वाले

श्रमिकों को अपने पास कार्य पर रख लिया था। एसके सेनापति रेलवे में सीनियर डीएमई के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा ठेका कार्य के संबंध में अनुबंध निष्पादित किया गया था। आरोपी आचार्य तत्कालीन सीडीओ रेलवे विभाग रायपुर द्वारा प्रदत्त बिलों को स्वीकार कर बिल पास कर दिया जाता था। आरोपी एसपी मीणा द्वारा सभी के खाते में बहुत ही कम वेतन ट्रांसफर किया गया था। एसपी मीणा द्वारा फर्जी बिल तथा वाउचर प्रस्तुत कर दिए जाते थे और बाकी आरोपी मिलकर उसका साथ दे रहे थे। परिवादी एवं अन्य श्रमिकों को उनका संपूर्ण वेतन कभी भी नहीं दिया गया। परिवादी को पता चला कि आरोपी गण द्वारा सुनियोजित षडयंत्र कर फर्जी लोन का स्टॉलमेंट संबंधी दस्तावेजों में दर्ज किया था और फर्जी तौर पर परिवादी एवं अन्य श्रमिकों के हस्ताक्षर बनाकर स्वयं कूटरचित दस्तावेज निर्मित किए गए थे। डायनेमिक एंटरप्राइजेज ठेका कंपनी के द्वारा नियम के विरुद्ध श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा था तथा श्रमिक कल्याण पोर्टल में भी गलत जानकारी प्रदान की जा रही थी। इस पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

गांजा खरीदने वाला बबलू महाराज जबलपुर से गिरफ्तार

राजनांदगांव। पुलिस थाना घुमका एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम ने गांजा आर्डर कर खरीदने वाले आरोपी मुकेश कुमार उर्फ बबलू महाराज को जबलपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घुमका थाना द्वारा धारा 20 (बी), (11) (सी) 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत पूर्व में मोहंदी चौक में 24 अक्टूबर 2024 को डीआई पिकअप वाहन में 65 किलोग्राम गांजा अवैध परिवहन करते 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर सोर्स टू एन्ड कार्रवाई करते संलिप्त अन्य 3 आरोपियों को ओडिशा, भिलाई और जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। गांजा आर्डर कर खरीदने वाले आरोपी बबलू महाराज निवासी जबलपुर जो कि कार्रवाई के बाद फरार हो गया था। पुलिस थाना घुमका एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम फरार आरोपी की पतासाजी के लिए जबलपुर रवाना हुई थी, जहां आरोपी के घर ग्राम देवनगर जिला जबलपुर आरोपी मुकेश कुमार उर्फ बबलू महाराज निवासी जबलपुर को हिरासत में थाना घुमका लाकर पूछताछ कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

कारोबारी के घर में दिनदहाड़े चोरी, लाखों का माल पार

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छांछी में चोरों ने व्यापारी के घर पर धावा बोलते हुए 10 लाख नकद, 20 लाख से ज्यादा के सोने-चांदी के जेवरात और नई क्रेटा कार सहित सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। चोरों ने दिनदहाड़े चोलेश उर्फ पिंटू साहू के घर को निशाना बनाया। साहू जो कसडोल के व्यापारी और गणपति एजेंसी के मालिक हैं, के घर से चोरों ने 10 लाख नकद, 20 लाख से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के गहने और नई क्रेटा कार चुरा ली। इतना ही नहीं, चोर सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे घटना की जांच में मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि दूसरी घटना देर रात 2:30 बजे की बताई जा रही है। जब घर खाली था, तब चोरों ने आराम से घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया। घटना के दौरान एक घर का ताला तोड़ते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ग्राम छांछी के अलावा कसडोल के राम जानकी नगर में भी तीन घरों के ताले टूटे पाए गए। चोरों ने सुनसान घरों को अपना निशाना बनाया।

दुकान में लगी आग, सिलेंडर में एक के बाद एक कई धमाके

दुर्ग। दुर्ग के छावनी थाना क्षेत्र के बैकुंठधाम जेपी नगर में एक कैटरिंग दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग में दुकान में रखे गैस सिलेंडर तक पहुंची और एक के बाद एक कई धमाके हो गए और 6 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल हो गया। आनन-फानन में लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की सूचना पर जिला प्रशासन की दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया गया। कैटरिंग की दुकान के बगल में वेल्डिंग शॉप है गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को फैलने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार कैटरिंग दुकान के मालिक ने दिल्ली से करीब 10 लाख से अधिक का कैटरिंग का सामान मंगवाया था। जो इस आग की चपेट में आने से सारा सामान जलकर राख हो गया।

नवविवाहिता ने जहर खाकर की आत्महत्या

कोरबा। कोरबा में कुसमुंडा थानांतर्गत नरईबोध गांव में रहने वाली एक नवविवाहिता ने जहर का सेवन कर खुदकुशी कर ली। डेढ़ वर्ष पूर्व उसनें अर्तजातीय प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ससुराल पक्ष छोटी जाति का हवाला देकर उसे प्रताड़ित करता था। मामला जब हद से गुजर गया तब नवविवाहिता ने जहर का सेवन कर लिया,जिससे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के कारण पुत्री की मौत होने का आरोप लगाया है। महिला का नाम काजल भारद्वाज है। ग्राम करमंदी निवासी काजल ने डेढ़ साल पहले ग्राम नरईबोध निवासी युवक से अंर्तजातीय प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था,लेकिन उसके बाद काजल को प्रताड़ित करने का दौर शुरु कर दिया गया। मृतका के पितानारायण भारद्वाज ने बताया कि छोटी जाति का हवाला देकर काजल को शारीरिक व मानिसक यातनाएं दी जाती थीं जिससे परेशान होकर काजल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

चलती मालगाड़ी के सामने कूदकर युवक ने दी जान

कोरबा। कोरबा में उरगा थाना अंतर्गत कोरबा चांपा रेलवे मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से सनसनी फैल गया। उरगा थाना के प्रधान आरक्षक राजेंद्र मरकाम के जानकारी अनुसार मंगलवार की रात बरपाली व मड़वारानी रेलवे स्टेशन के मध्य एक युवक का शव बरामद हुआ है । युवक का पहचान के लिए कोई भी दस्तावेज या कोई सामान नहीं मिला है। पुलिस शव को बरामद कर जिला अस्पताल के मर्चुरी भेज दिया गया है और आसपास के लोग को युवक का पहचान की कोशिश की जा रही है। मालगाड़ी के ड्राइवर ने इस घटना की सूचना आरपीएफ थाना पुलिस को दी। गुरुवार की रात लगभग 12:00 बजे रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक पैदल चल रहा था उसे देखकर ड्राइवर के द्वारा हॉर्न बजाया गया उसे लगा कि युवक किनारे हो जाएगा लेकिन मालगाड़ी जब युवक के पास पहुंचा इस दौरान चलती मालगाड़ी के नीचे वह कूद गया जहां इसकी सूचना उसने तत्काल आरपीएफ पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही उरगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

बरौदा सोसायटी को कंगाल बनाने पर तुले हैं शासन और किसान

आरंग। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के मंदिर हसौद शाखा के अधीन आने वाले बरौदा सोसायटी के माली हालत की फिक्र न शासन को है और न ही यहां धान बेचने वाले किसानों को। इन दोनों के रुख से लगता है कि वे मिलकर सोसायटी को कंगाल बनाने में तुले हैं। इस सोसायटी के धान उपार्जन केन्द्र में धान बेचने के लिये तकरीबन 160 किसान पंजीकृत हैं जिनसे केवल लगभग 8 हजार क्विंटल धान खरीदी किया जाना है पर धान खरीदी शुरू होने के 64 दिनों बाद भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है और इस पर तुर्रा यह कि प्रतिदिन धान खरीदी की सीमा तय कर दिये जाने की वजह से तीन टोकन का उपयोग कर लेने के बाद भी एक किसान शेष धान को बेचने टोकन जारी करने की मांग को ले खाद्य विभाग का चक्कर

काट रहा है।

इस धान उपार्जन केन्द्र का दौरा करने के बाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है कि सोसायटी के अंतर्गत 8 ग्राम बरौदा, राखी, चीचा, कयाबांधा, झांझ, नवागांव व खपरी आता है। नया राजधानी के नाम पर इन ग्रामों के खेती की अधिकतर भूमि को शासन द्वारा कब्जियाने के कारण कभी गुलजार रहने वाले इस समिति में इस खरीदी सत्र में धान बेचने महज 160 के आसपास किसान पंजीकृत हैं और पात्रतानुसार इनसे लगभग 8 हजार क्विंटल धान खरीदी किया जाना है पर 64 दिनों में महज 6 हजार क्विंटल धान की खरीदी ही हो पायी है। शासन द्वारा प्रतिदिन धान खरीदी की सीमा 181 क्विंटल कर दिये जाने व इसमें से महज 30 प्रतिशत ही बड़े किसान का खरीदने की नीति के चलते एक बड़े किसान द्वारा निर्धारित 3 टोकनों का उपयोग कर लेने के बाद भी शेष बचे करीबन 5 सौ क्विंटल धान बेचना बाकी रह गया है जिस हेतु समिति द्वारा खाद्य विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है और किसान खाद्य विभाग का चक्कर काट रहा है।

इस समिति के विशेष परिस्थितियों को अनदेखा कर प्रतिदिन धान खरीदी के लक्ष्य को न बढ़ाये जाने व किसानों द्वारा एकमत हो स्वमेव दिन नियत कर एकसाथ धान न लाने के साथ - साथ परिवहन न होने की वजह से पूरे ढाई माह खरीदी केंद्र खुले रखने की मजबूरी के चलते समिति को अनावश्यक खर्च वहन करने मजबूर होने की जानकारी देते हुये शासन से प्रतिदिन धान खरीदी का लक्ष्य शिथिल करने, परिवहन हेतु शेष बचे धान का प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र उठाव करने व किसानों को शासन के नियमों के चलते शेष बचे धान की बिक्री में आ रही दिक्कतों को दूर करने की मांग की है। साथ ही शेष बचे किसानों को एकराय हो दिन निर्धारित कर एकसाथ धान उपार्जन केन्द्र में लाने का आग्रह किया है ताकि समिति को और अधिक आर्थिक क्षति न पहुंचे।

तीन जीआरपी आरक्षकों की करोड़ों की संपत्ति जब्त

बिलासपुर। जीआरपी के तीन आरक्षकों की डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। तीनों आरक्षकों पर गांजा तस्करी का आरोप था।जिसके बाद पुलिस की जांच में आरोप सही पाए गए।इसके बाद आरक्षकों की काली कमाई पर शिकंजा कसा गया। काली कमाई करने वाले जीआरपी के तीन आरक्षकों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला ।जांच के बाद तीनों आरक्षकों की जमीन, वाहन सहित डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।मामले का प्रतिवेदन मुंबई के सफेमा कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल आरक्षक जेल में बंद है।

आरक्षकों की गांजा तस्करी में थी अहम भूमिका = बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर 2023 को जीआरपी पुलिस ने योगेश सोंधिया और रोहित त्रिवेदी को पकड़कर

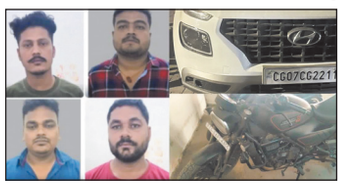

उनके कब्जे से 20 किलो गांजा बरामद किया था। एटीएस की टीम ने मामले की जांच की। जिसमें जीआरपी आरक्षकों की संलिप्तता उजागर हुई थी। डीजीपी अशोक जुनेजा ने एसपी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। उनके निर्देश पर एसीसीयू की टीम ने जांच के बाद जीआरपी के आरक्षक लक्ष्मण गाईन,मन्नु प्रजापति,संतोष राठौड़, सौरभ नागवंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसपी रजनीश सिंह ने बताया पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इनकी संपत्तियों को जब्त किया है। जिसमें सिरगिट्टी और कोरबा की जमीन, मकान, और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, टाटा सफारी जैसी लक्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं।मोटर साइकिल की ही कीमत 4 से 5 लाख है।इसके अलावा इन्होंने अलग-अलग सिम में यूपीआई आईडी बनाई थी।जो इन्हीं के नाम पर थी।अपराधियों ने बताया कि उन्होंने गांजा डिलिवर होने के बाद उसी तारीख को इनके बैंक अकाउंट में पैसों का ट्रांजेक्शन किया है। अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस मामले को मुंबई के सफेमा कोर्ट में भेजा गया है। एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थ में एंड टू एंड कार्रवाई के तहत एसीसीयू के आरक्षकों ने गाजे से कमाई गई संपत्ति की जांच शुरू की।जिसमें आरक्षक लक्ष्मण गाईन, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौड़ के पास जमीन वाहन सहित करीब डेढ़ करोड़ की संपत्ति थी।

संक्षिप्त समाचार

निकाय चुनाव के लिए चेहरे तय करना आसान नहीं

रायपुर। निकाय चुनाव के लिए बस एक दो दिन में आचार संहिता लगने वाली है मतलब चुनाव की तारीख घोषित होते ही प्रत्याशी भी जल्द घोषित करना पड़ेगा। संभावना ये है कि पहली मार्च से पहले-पहले चुनाव संपन्न करा लेना है, मतलब चुनाव के लिए समय काफी कम रहेगा। ज्यादा अपेक्षाएं दावेदारों ने पाल रखी है इसलिए भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए चेहरे तय करना मुश्किल भरा काम है। गुहार, जुगाड़, आवेदन, बायोडाटा तो चल ही रहा है, प्रचार प्रसार भी अघोषित रूप से शुरु कर दिया गया है। न केवल पार्षद बल्कि महापौर, जिपं अध्यक्ष के लिए भी घमासान मचना तय है। सूची काफी लंबी है। चुनाव आते-आते यह और बढ़ जायेगी। सत्ता पक्ष होने से भाजपा में उत्साह ज्यादा है, वहीं कांग्रेस में लोकसभा-विधानसभा हारने के बाद माहौल में कोई बदलाव नहीं देख दावेदार ये भी मान कर चल रहे हैं कि नहीं मिली तो भी ठीक। अभी तो सभी कह रहे हैं कि मेरा तो पक्का है, तो कच्चा किसका है ये जानने कुछ दिन इंतजार कर लें।

अंगूठा छाप पूर्व मंत्री आखिर 2 करोड़ को खपाता कहां था

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच जब से ईडी ने शुरु की है रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा जानकारी में ईडी बता रहा है कि पूर्व आबकारी मंत्री को 2 करोड़ रुपए हर महीने जाता था। आखिर इतनी बड़ी रकम अंगूठा छाप मंत्री खपाता कहां रहा होगा? या तो परिवार का कोई सदस्य या कोई सलाहकार या कोई और.. क्योंकि सीए तो एक माध्यम होता है एडजस्टमेंट करने के लिए। गिरफ्तारी के बाद जो संभावना जतायी जा रही है या तो अंगूठा छाप को कुछ परसेंट देकर बाकी बड़े खिलाड़ी डकार जाते रहे होंगे। लेकिन ईडी की घेरेबंदी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, निश्चित रुप से वो सभी चेहरे भी बेनकाब होंगे, लेकिन अंगूठा छाप का कारनामा तो गिनीज बुक में दर्ज होने लायक है, जो हर माह 2 करोड़ लेकर भी कह रहा है कि मैंने फूटी कौड़ी नहीं ली।

महिला टीचर्स ने समायोजन की मांग को लेकर वित्त मंत्री के बंगला का किया घेराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। नौकरी से निकालने के बाद वे समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब महिला टीचर्स हजारों की संख्या में सुबह समायोजन की मांग को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला घेर लिया। इस दौरान उन्होंने जमकर समायोजन की नारे लगाए। बता दें कि विगत दिनों से बीएड सहायक शिक्षक राज्य सरकार से अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने वित्त मंत्री के घेराव किया और अपनी मांगे राखी। सहायक शिक्षकों का कहना है कि वे विगत दिनों से समायोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मांग को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। सहायक शिक्षकों का कहना है कि वे सर्द रात में भी अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका परिवार भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे और पत्नी, बेटी की वजह से उन्हें भी शामिल होना पड़ रहा है। वहीं बीएड सहायक शिक्षकों का विपक्ष पार्टी के नेताओं ने भी समर्थन किया है।

रेना उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग व वासु जिपं सक्ति के सीईओ नियुक्त

रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सुश्री रेना जमील, भा.प्र.से. (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलरामपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा वासु जैन, भा.प्र.से. (2021), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर, जिला-नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सक्ति के पद पर पदस्थ किया है।

तेंदूपत्ता खरीदी सीजन शुरू होने से पहले 89 सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति

रायपुर। तेंदूपत्ता खरीदी सीजन शुरू होने से पहले राज्य लघु वनोपज संघ ने एक वर्ष की संविदा अवधि के लिए 89 सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति की है। इनमें सहायक प्रबंधक उपार्जन पर 50, प्रबंधन 7, निर्माण 7 और सहायक प्रबंधक 25 शामिल हैं। इन्हें 37500 एक मुश्त वेतन देय होगा इसके अलावा कोई भी भत्ते, पेंशन, मृत्यु लाभ नहीं मिलेगा। एक वर्ष की सेवावधि बाद कार्यकाल का आंकलन कर पुन एक वर्ष सेवा विधि बढ़ाई जा सकेगी। दोनों पक्ष एक माह की सूचना देकर सेवा से पृथक हो सकेंगे।

कलेक्टर दर पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की मजदूरी दर स्वीकृत

कांकेर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रशासनिक मद से कलेक्टर दर पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की मजदूरी कलेक्टर दर के आधार पर अक्टूबर एवं नवम्बर का एरियर्स तथा माह दिसम्बर का वेतन की राशि 51 हजार 824 रूपए स्वीकृत की गई है। उक्त राशि जिला पंचायत कांकेर, जनपद पंचायत अंतागढ़, चारामा और कोयलीबेड़ा हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रशासनिक मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगी।

तकनीकी शिक्षा और सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन, सीआईआई यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुआ एमओयू

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने पूरी तरह प्रतिबद्ध : शर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आज शहीद स्मारक ऑडिटोरियम, रायपुर में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मुख्य आतिथ्य में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव श्री एस भारतीदासन ने सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन, सीआईआई यंग इंडियंस और अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर संचालक तकनीकी शिक्षा और रोजगार श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉ प्रीतसिंह, सीएसआरबॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनो विराज सिंह, वाईस प्रेजिडेंट और सीआईआई यंग इंडियंस के चेयर पर्सन श्री गौरव अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न संस्थान के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

अनुबंध निष्पादन समारोह के अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का यह अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र चाहे वह आईटीआई से हो इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलीटेक्निक से उसके पास रोजगार का उचित अवसर हो। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि रोजगार के लिए पंजीकृत छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह केवल राज्य के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि अनुबंध के तहत जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, वे पूर्ण पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से सीजी रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप एक सही दिशा मिले। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए यह सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अपनाटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीएसआरबॉक्स और सीआईआई यंग इंडियंस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार और कौशल विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। आईबीएम द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स करवाया जाएगा जो राज्य के आईटीआई, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध होगा। इस कोर्स से छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और कम से कम 10त्न छात्रों को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि युवा अगर चाहे तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल एक विचार से शुरू होता है। हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि वे केवल वही न बनाएं जो पहले से बाजार में है, बल्कि ऐसे नए उत्पाद और समाधान तैयार करें, जो समाज के लिए उपयोगी हों। एक छोटी सोच को बड़ा लक्ष्य बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी।

वन एवं कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता है। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।

मोवा ओवरब्रिज मरम्मत कार्य में गडबड़ी पर पांच अधिकारी निलंबित

रायपुर। लोक निर्माण विभाग ने रायपुर के मोवा रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत में अमानक एवं गुणवत्ताहीन कार्य तथा अनियमितता पर भी बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद विभाग ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। ओवरब्रिज में डामरीकरण कार्य में शिकायतों का संज्ञान लेकर उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने कार्य का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर गुणवत्ताहीन कार्य/खराबी पाई थी।

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सेतु परिक्षेत्र, रायपुर के मुख्य अभियंता द्वारा केन्द्रीय गुणवत्ता एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त की गई, जिसमें औसत बिटुमिन कंटेंट, कंबाईन्ड डेन्सिटी, मटेरियल के ग्रेडेशन मानक स्तर से कम पाया गया। इस प्रकार अमानक स्तर एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण का कार्य कराया जाकर कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंताओं द्वारा अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग ने कार्यपालन अभियंता विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी रोशन कुमार साहू तथा उप अभियंता राजीव मिश्रा,देवव्रत यमराज और तन्मय गुप्ता को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन सभी का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

उपमुख्यमंत्री को अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महंगाई भत्ते को जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत बढ़ाने सहित पांच सूत्रीय मांगें शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा एवं प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री को कर्मचारियों की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान की आवश्यकता को विस्तारपूर्वक बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र, जिसे मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया गया था, में किए गए वादों को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया गया। फेडरेशन ने अपने आंदोलन झन करव इनकार, हमर सुनव सरकार के बारे में भी जानकारी दी।

ये हैं प्रमुख मांगें

1. प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप केंद्र के समान देय तिथि से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते का एरियर भविष्य निधि खाते में समायोजित किया जाए।

2. विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

3. प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 एवं 32 वर्षों की सेवा पर प्रदान किया जाए।

4. मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिवस किया जाए।

5. शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए, राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए।

पुलिस महकमे में फेरबदल की सुगबुगाहट, दूरस्थ इलाकों से होगी कई की वापसी

रायपुर। सूबे के पुलिस महकमे में किसी भी क्षण फेरबदल की संभावना बतायी जा रही है। इसलिए कि सरकार बदलने के बाद भी दूरस्थ इलाकों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे पुलिस अफसरों की अब प्रमुख व संवेदनशील पदों पर वापसी की गुंजाइश बन रही है। किसी भी क्षण आदेश निकलने की चर्चा तेज हैं।

छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग का बहुप्रतीक्षित फेरबदल एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ इलाकों में भेजे गए राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अब प्रमुख और संवेदनशील पदों पर वापसी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों का कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से करीबी रिश्ता था, जिसके कारण उन्हें पहले हाशिए पर धकेल दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, इस फेरबदल में करीब 30 एसपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी प्रमुख हैं। कहा जा रहा है कि इस सूची को पहले अंतिम रूप दे दिया गया था, जिसमें कई अधिकारियों को संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिलों में तैनात करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, टीआई (थाना प्रभारी) रैंक के अधिकारियों के नए पदस्थापना आदेश भी इस सूची का हिस्सा होंगे। पिछली बार दिसंबर 2024 में 12 और 27 तारीख को जारी हुए टीआई के तबादला आदेशों ने काफी विवाद खड़ा किया था। इन आदेशों से विभागीय असंतोष इतना बढ़ गया था कि कई वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी ऐसे ही विवाद सामने न आए इसलिए सूची को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। सूची किसी कारणवश अटक गई या संशोधन हो गया तो इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता।

दुर्ग व भिलाई स्टेशन में फास्ट फूड यूनिट की सुविधा जल्द

रायपुर। रेलवे द्वारा यात्रियों के खानपान अनुभव को और भी बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यात्रियों के लिए बेहतर खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रायपुर रेल मंडल के दुर्ग व भिलाई पावर हाउस स्टेशन में फास्ट फूड यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं । इन यूनिट्स के माध्यम से यात्रियों को स्टेशन पर ही गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ खानपान की सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अंतर्गत दुर्ग स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2/3 में फास्ट फूड यूनिट व भिलाई पावर हाउस स्टेशन स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 में फास्ट फूड यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं । रेलवे प्रशासन द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन दोनों स्टेशनों के फास्ट फूड यूनिट्स की सुविधा दी जा रही है, यह सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए है, जो त्वरित सेवा के साथ स्वादिष्ट फास्ट फूड का आनंद लेना चाहते हैं।

युवती की हत्या पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार

रायपुर। कमल विहार में चार दिन पहले मिली युवती की अर्द्धनग्न लाश के मामले में अब तक पुलिस के आरोपियों तक नहीं पहुंच पाने पर कांग्रेस विरोध-प्रदर्शन कर रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के गेट के सामने युवती की फोटो हाथों में लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में शहर जिला कांग्रेस पार्टी कमेटी के नेतृत्व में गृह मंत्री के घर का घेराव करेगी। और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे। बता दें कि टिकरापारा थाना क्षेत्र के कमल विहार सेक्टर-1 इलाके में चार दिन पहले एक युवती की अर्द्धनग्न लाश मिली थी। स्थिति को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई थी। यही नहीं प्रथम दृष्टया पुलिस ने माना था कि युवती की हत्या कहीं और कर गुमराह करने की नियत से उसे कमल विहार में फेंका गया है।

शराब दुकान का शटर उखाड़ कर अलग-अलग ब्रांड के 144 बोतल लेकर हुए फरार, छह गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इस बार सूने मकान या घर में नहीं बल्कि शराब दुकान में चोरों ने चोरी की है। दरअसल, चोर महंगी शराब के शौक़ीन थे। शौक पूरा करने के लिए शराब दुकान पहुंच गए और शटर उखाड़ कर दुकान अंदर घुस गए। इतना ही नहीं आरोपियों ने अलग-अलग ब्रांड के 144 बोतल लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने चार नाबालिग समेत छह को गिरफ्तार किया है।

पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की दो बाइक भी जब्त की है, जिसे चोरों ने शोरूम से चुराया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, चोर महंगे शराब पीने के शौक पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम दिया है।

मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि जितेश कुमार बांधे ने खमतराई थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह व्यास तालाब बिरगांव के विदेशी शराब दुकान में चीफ सेलर के पद पर पदस्थ है। वह 14 जनवरी को दुकान बंद करके घर चला गया। अगले दिन सुबह उसे दुकान के गार्ड ने सूचना दी कि दुकान में चोरों ने शटर को उखाड़ कर चोरी कर ली है। जिसमें अलग- अलग ब्रांड की 144 बोतल शराब चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई।

इस मामले को लेकर पुलिस ने खोजबीन की, जिसके बाद सबसे पहले आरोपी राजा देवार, विकास देवार को पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने चार नाबालिगों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट नगर की विदेशी शराब दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो चोरी की बाइक भी जब्त की है। जिसे उन्होंने भिलाई के शोरूम से चुराया था।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, दन्तेवाड़ा
(फोन / फैक्स नं.- 07856-252362, ई- मेल- eedan-phe-cg@nic.in)

ऑनलाईन निविदा निरस्तीकरण सूचना

जी क्रमांक 242504428

इस कार्यालय द्वारा नीचे दर्शित कॉलम अनुसार निम्नलिखित ऑनलाईन निविदा में निविदाकार द्वारा दर ज्यादा होने के कारण निरस्त किया जाता हैं। विवरण निम्नानुसार है।

स. क्र.	निविदा सिस्टम कमांक
1	system no- 162505, 162506

जी क्रमांक- 242504428

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
दंतेवाड़ा

जी-242505411/4

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)

निविदा सूचना
(प्रथम आमंत्रण)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

एन.आई.टी. क्र. / सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू (लाख में)
1	2	3
219/159167	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के रिसर्च गर्ल्स हॉस्टल भवन (भूतल एवं प्रथम तल) के जीर्णोद्धार कार्य।	3 रू. 43.85 लाख
218/163817	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कम्यूनिटी भवन के प्रस्तावित आहाता ड्रेन कवर, एन.पी. 3 पाईप कार्य।	रू. 48.08 लाख
217/163818	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कम्यूनिटी भवन के भूतल में जीर्णोद्धार कार्य।	रू. 46.89 लाख

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.02.2025 समय सायं 5:30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्र.-1. रायपुर (छ.ग.)

जी-242505410/4

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर

(केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ट) ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

Main Portal: https: // eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	सिस्टम निविदा क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
1	164431 प्रथम आमंत्रण 16.01.2025	जिला रायपुर के रायपुर शहर के अंतर्गत रिंग रोड क्र. 02 में जरवाय मार्ग बंगाली होटल के पास ओव्हर पास का निर्माण कार्य।	1542.84
2	164441 प्रथम आमंत्रण 16.01.2025	जगदलपुर एयरपोर्ट में आईसोलेशन बे निर्माण कार्य ।	727.37
3	164452 प्रथम आमंत्रण 16.01.2025	जगदलपुर एयर स्ट्रीप में रायडिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट (पिरेडिक रिनीवल) निर्माण कार्य।	1104.29
4	164447 प्रथम आमंत्रण 16.01.2025	जिला रायपुर के रिंग रोड क्रं-2 में सरोरा चौक पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप ओव्हरपास का निर्माण कार्य।	3686.24
5	164425 द्वितीय आमंत्रण 16.01.2025	जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पड़कीभाट-रावन-सकलोर-हिरमी मार्ग लंबाई 15.00 कि.मी. में मजबूतीकरण निर्माण कार्य, पुल-पुलिया सहित।	3091.50
6	164448 प्रथम आमंत्रण 16.01.2025	जिला रायपुर के रिंग रोड क्रं-02 के हीरापुर चौक रायपुर में ओव्हर पास का निर्माण कार्य ।	3446.97

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि सं.क्र. 05 दिनांक 03.02.2025 निर्धारित है। एवं अन्य शेष निविदाओं के लिए दिनांक 06.02.2025 निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

मुख्य अभियंता
केन्द्रीय निविदा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर

जी-242505443/11

इजरायली हमलों से थर्राया गाजा

अभिनय आकाश

460 दिनों के बाद गाजा में चल रही मुसलसल जंग आखिरकार के थमने का रास्ता खुल गया है। 15 जनवरी की देर रात कतर के प्रधानमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि हमास और इजरायल ने युद्ध विराम की शर्तें मान ली है। युद्ध विराम की बात तो जंग की शरुआत के साथ ही चल रही थी इसके पहले नवबंर 2023 में एक ट्रेपररी सीजफायर भी हुआ था। जिसमें 50 इजरायली बंधक और 150 इजरायली कैदी रिहा किए गए थे। लेकिन ये युद्धविराम महज चार दिन तक चल सका। इसके बाद हमले फिर से शुरू हो गए। इन हमलों में अब तक 47 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं । इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जंग रोकने का दबाव बढ़ रहा था। इजरायल के कट्टर दक्षिणपंथी नेता इस डील से नाखुश हैं। कह रहे हैं कि ये समझौता हमास के सामने हथियार डालने जैसा है। वहीं हमास और इजरायल के बीच सीजफायर के कुछ ही घंटों के बाद गाजा इजरायली हमलों से थर्रा उठा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अलग अलग हमलों में 80 लोग मारे गए। 19 जनवरी से जंग को रोकने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जंग तीन चरणों में खत्म की जाएगी। पहला चरण 42 दिनों तक चलेगा जिसमें हमास इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। वहीं इजरायल को हमास और फिलिस्तिनियों को अपनी जेल से रिहा करना होगा। दूसरे चरण में कुछ और इजरायली बंधक छोड़े जाएंगे और इजरायल को पूरा गाजा खाली करना होगा। इसके बाद तीसरे चरण में इजरायल और फिलिस्तीन के भविष्य पर चर्चा होगी। इस सहमति के पीछे अमेरिका की भूमिका तो है ही, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का इसमें निजी दिलचस्पी लेना भी खासा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि उनके पद ग्रहण करने से पहले बंधक छोड़ दिए जाने चाहिए। सहमति बनने की घोषणा भी सबसे पहले ट्रंप ने ही की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने डॉनल्ड ट्रंप की तारीफ की और कहा कि युद्धविराम समझौते के लिए उनकी भूमिका अहम रही है। मिलर ने एक प्रेस ब्रीफ में कहा कि सौदे को अंतिम रूप देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि जाहिर है कि इस प्रशासन का कार्यकाल 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। हम समझौते पर हमारे साथ काम करने के लिए ट्रंप टीम को धन्यवाद देते हैं। इस कथित सहमति को लेकर कई सारे सवाल बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि अगर सहमति पर दोनों पक्ष कायम रहे और इस पर अमल शुरू हुआ तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इससे स्थायी शांति कायम हो ही जाएगी। पहले छह हफ्ते के युद्धविराम के दौरान जहां 33 बंधक छोड़े जाने है, वहीं स्थायी युद्धविराम की शर्तों पर बातचीत शुरू होनी है। आगे चलकर सारे बंधक छोड़े जाने की बात है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कितने जीवित है। युद्धविराम के बाद गाजा में शासन की क्या और कैसी व्यवस्था होगी, यह भी तय होना बाकी है। इस बड़ी घटना पर भारत का बयान भी सामने आया है। इजरायल और हमास के बीच जो शांति डील हुई है उसका भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। गाजा में संघर्ष विराम समझौते का भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते है। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को निरंतर मानवीय सहायता मिलेगी। चीन ने भी स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने समझौते का स्वागत करते हुए मध्यस्थों - मित्र, कतर और अमेरिका के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। इस समझैते और युद्ध रुकने के बाद भारत व देश के अन्य लोगों के लिए कई रणनीतिक अवसर पैदा होंगे। ऐसी ही एक परियोजना आईएमईसी (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) 7 अक्टूबर के हमले के कारण रुक गई थी। अब युद्धविराम के बाद इसके फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना पर आठ देशोंः भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। आईएमईसी परियोजना हमारे लिए कई भू-राजनीतिक और आर्थिक लाभों के साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक सहयोग बढ़ाने और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश (पीजीआईआई) के लिए साझेदारी का हिस्सा बनने पर केंद्रित है। आईएमईसी अब भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक एक आर्थिक गलियारे के रूप में आगे बढ़ेगा। इसे चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह शिपिंग और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से संचार और परिवहन चैनलों को मजबूत करेगा। मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता से राहत मिलने के साथ, भारत ने राहत की सांस ली है।

'आप' तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करेगी?

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली विधानसभा चुनावों को एक बार फिर जीतने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी वोट मांगने के दौरान अपनी मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में तो जनता को बता ही रही है साथ ही वह संविधान और लोकतंत्र की दुहाई भी दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से दी गयी मुफ्त की सौगातें बड़ा छलावा साबित हुई हैं और लोकतंत्र तथा संविधान की मर्यादा का भी इस पार्टी की सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा।

आप देख रहे होंगे कि आजकल अरविंद केजरीवाल रोज प्रेस के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले पांच सालों में इन्होंने कुछ काम नहीं किया और सारा वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से लड़ने में बर्बाद कर दिया। जिस विधानसभा को दिल्ली के लोगों की समस्याओं का हल निकालना था उसको आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का मंच बनाकर रख दिया। दिल्ली विधानसभा को किस तरह आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का मंच बना कर रखा इसे आप इसी से समझ सकते हैं कि निवर्तमान विधानसभा ने पूरे पांच साल में मात्र 74 दिन ही कार्य किया। पांच साल में 1825 दिन होते हैं मगर इनमें से काम हुआ मात्र 74 दिन। हम आपको बता दें कि यह दिल्ली की विधानसभा के अब तक के सबसे कम कार्य दिवस का रिकॉर्ड है। इसके अलावा बड़ी-बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरे पांच साल में मात्र 14 विधेयक पारित किये। यानि दिल्ली की विधानसभा ने अपने इतिहास में पांच साल में सबसे कम विधेयक पारित करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। खास बात यह रही कि यह जो 14 विधेयक पारित हुए उनमें से पांच विधायकों के भत्ते, सुविधाएं और उन्हें मिलने वाली सैलरी से संबंधित थे। साथ ही दिल्ली के विधायकों के कामकाज का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 से 2025 तक विधायकों ने विधानसभा में सालाना आधार पर औसत 219 प्रश्न ही पूछे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के शासन में विधानसभा में जिस दिन भी कार्यवाही हुई वह औसतन मात्र तीन घंटे तक चली। इसके अलावा विधानसभा के 74 कार्य दिवसों में से मात्र नौ दिन ही प्रश्नकाल हुआ।

यही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी विधानसभा का सत्रावसान भी नहीं किया ताकि जब चाहें विधानसभा की बैठक बुला सकें और वहां से राजनीतिक बयानबाजी कर सकें। दरअसल विधानसभा का सत्रावसान होने पर सत्र को दोबारा आहूत करने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति चाहिए होती है और उन्हें सदन की बैठक बुलाने का कारण भी बताना होता है। आम आदमी पार्टी को लगता था कि यदि उपराज्यपाल ने बैठक बुलाने की अनुमति नहीं दी तो कैसे अपने राजनीतिक हित सधेंगे इसलिए वह कभी सत्रावसान करते ही नहीं थे। यही नहीं, विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी थीं वह भी नहीं की गयीं।

जहां तक आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से बांटी जाने वाली मुफ्त रेवड़ियों की बात है तो उसकी सच्चाई यह है कि जनता को जितना दिया नहीं गया उतना हर योजना में घोटाला हो गया है। यह घोटाले भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके के हैं। मसलन एक दारू की बोतल पर दूसरी बोतल फ्री दी गयी लेकिन शराब नीति के जरिये घोटाला करके दिल्ली के सरकारी खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गयी लेकिन एक यूनिट फालतू होते ही भारी भरकम बिजली बिल भेजे गये। जनता को 700 लीटर पानी फ्री देने की बात हुई लेकिन लोगों के भारी भरकम पानी के बिल आये। खास बात यह रही कि पानी का बिल तो हर महीने आ गया लेकिन नल से जल हर रोज नहीं आया और जहां जहां नल से जल आया वह गंदा आया।

इसके अलावा प्रदूषण से निबटने की कोई स्थायी और प्रभावी योजना नहीं होने के चलते दिल्ली इतनी प्रदूषित हो गयी कि लोगों को तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो गयी हैं। अक्सर बुजुर्गों को होने वाली सांस की बीमारी दिल्ली के बच्चों को भी हो गयी है। दिल्ली में पवित्र यमुना नदी को गंदा नाला बनने से रोकने में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल रही। दिल्ली में यमुना का जल इतना प्रदूषित है कि त्योहारों पर श्रद्धालु अगर पानी में चले जायें तो उन्हें चर्म रोग हो जाते हैं और इस पानी का शोधन करने में मशीनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। यही नहीं, दिल्ली की सरकार अपने शिक्षा मॉडल का ढिंढोरा खूब पीटती है लेकिन अपने अब तक के कार्यकाल में वह एक भी नया स्कूल, एक भी नया कॉलेज या एक भी नया अस्पताल नहीं बना सकी है। दिल्ली में जल निकासी की व्यवस्था इतनी खराब है कि बारिश आने पर बेसमेंट में पानी भर जाने से छात्र डूब कर मर जाते हैं। यही नहीं, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी का शासन होने के बावजूद कूड़े के पहाड़ वहीं के वहीं हैं।

इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल भले इस समय मंदिर मंदिर जाकर हिंदुओं को लुभाने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन तथ्य यह है कि आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान ही हिंदू दीवाली पर पटाखे नहीं चला पाये। यह बात भी गौर करने लायक है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को अभी 1000 रुपए मासिक देने और चुनाव बाद 2100 रुपए देने की बात कर रही है लेकिन सवाल उठता है कि महिलाओं की सुध उसे अपने शासन की शुरुआत या मध्य में क्यों नहीं आई थी? यही नहीं, एक दारू की बोतल पर दूसरी दारू की बोतल फ्री देकर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं का ही सिरदर्द सबसे ज्यादा बढ़ाया था।

वैसे यहां सवाल आम आदमी पार्टी से ही नहीं है बल्कि दिल्ली के मतदाताओं से भी है। आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र में किये गये फ्री के वादों को देखने की बजाय क्या किसी मतदाता ने इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा है। दिल्ली के मतदाताओं को यह जानकर हैरानी होगी कि अपने घोषणापत्र का प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश कर रही है क्योंकि रिपोर्ट में दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं।

दिल्ली के मतदाताओं पर देश की नजर इसलिए भी है क्योंकि नवीनतम सांख्यिकीय पुस्तिका दर्शाती है कि साल 2023-24 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,61,910 रुपये थी जो देश में गोवा और सिक्किम के बाद तीसरी सबसे अधिक है। यानि शहर की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय 1,84,205 रुपये से दोगुनी से भी अधिक थी। इसके अलावा एक और आंकड़ा यह बताता है कि सबसे कम महंगाई दर के मामले में झारखंड के बाद दिल्ली का नंबर आता है। यानि दिल्ली में आमदनी ज्यादा है और महंगाई कम है इसलिए सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में भी सबको सब कुछ फ्री में क्यों चाहिए? देश की जनता देख रही है कि क्या दिल्ली का मतदाता अपने निजी फायदे पर ध्यान देने की बजाय इस बार अपने शहर के फायदे को देखेगा?

एकात्मता के स्वर — पंचमहाभूत

पाँच महाभूतों से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। महाभूतानि खं वायुरग्निपस्तथा च भूः। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पंचमहाभूतों का अपना-अपना एक गुण है शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ।। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पृथ्वी में पाँच गुण-शब्द, स्पर्श, रूप और गंध है।

जल में चार गुण-शब्द, स्पर्श, रूप और रस है। अग्नि (तेज) में तीन गुण-शब्द, स्पर्श, रूप है। वायु के दो गुण-शब्द और स्पर्श। आकाश में एक ही गुण है आकाश। लोकप्रतिष्ठित करने वाले पाँचों भूतों में पंद्रह गुण बताये गये हैं। आनुपूर्व्या विनश्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः ।। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते हैं और क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम में लय होता है और आकाशादि के क्रम में उत्पन्न होते हैं। प्राणियों का शरीर इन पाँच महाभूतों का ही संघात है। इसमें चेष्टा या गति है वह वायु का भाग है।

जो खोखलापन है, वह आकाश का अंश है। ऊष्मा (गर्मी) अग्नि का अंश है। रक्तादि तरल पदार्थ है वह जल अंश है और हड्डी, मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं।

इन्हीं के सूक्ष्म अंश श्रोत्र (कान), घ्राण (नासिका), रसना (जिह्वा), त्वचा और नेत्र ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। शरीर में त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा और स्नायु पृथ्वी से त्वचा, क्रोध, नेत्र, ऊष्मा और जठरानल ये पाँच अग्नि से, कान, नासिका, मुख, हृदय और उदर यह आकाश से, कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी और रुधिर ये पाँच वस्तुएँ जलरूप है। पृथ्वी के गुण गन्ध के नी भेद हैं, जल के छह भेद, अग्नि (रूप) के सोलह भेद, वायु (स्पर्श) के बारह भेद तथा आकाश (शब्द) के सात भेद कहे गये हैं। शब्द श्रोत्रेन्द्रिय तथा शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्राण, चेष्टा व स्पर्श वायु से रूप, नेत्र, जठरानल अग्नि से रस, रसना और स्नेह जल से व गंध, नासिका और शरीर यह तीनों ही भूमि के गुण हैं। इस प्रकार इन्द्रिय समुदाय सहित यह शरीर पांचभौतिक बताया गया है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

अन्यथा व्याकरण-रीति से यौगिक शब्दार्थ कर डालने पर तो उल्टा अर्थ का अनर्थ हो जाने की अधिक सम्भावना है। व्याकरणगत-घि, टि, संप्रसारण, आदेश, पूर्व, पर, नित्य, अन्तरङ्ग, अपवाद, अनुबन्ध और प्रत्याहार आदि शब्दों का; ज्योतिष के- कण्टक, पणफर, आपोल्किम, भाव, सन्धि विशोपका, अन्तर और प्रत्यन्तर आदि शब्दों का आयुर्वेद के अतिसार, प्रमेह, उदावर्त और पूर्वरूप आदि शब्दों का वेदान्त के अभिन्ननिमित्तोपादान, विवर्त, उपाधि और अर्थापत्ति आदि शब्दों का; न्याय के- व्याप्ति, अवच्छेदक, अवछिन्न और पारिमाण्डल्य आदि शब्दों का; मीमांसा के- परिसंख्या, औपपत्तिक, अर्थवाद और कैमुतिक आदि शब्दों का; अलङ्कार शास्त्र के- विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, रस और रीति आदि शब्दों का-यौगिक अर्थ कल्पना करने पर कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। उक्त शब्दों की सीमा कितनी व्यापक है और इनके प्रयोग से कितने विस्तृत तात्पर्य का बोध होता है, इस रहस्य का पता उन्हीं ग्रन्थों के पढ़ने पर लग सकता है, जिनमें कि ये शब्द प्रयुक्त होते हों । इस प्रकार प्रत्येक शास्त्र में विलक्षण शब्दों के समावेश से वाक्य, वाक्यार्थ-वलक्षण्य को हम %शैली% नाम से स्मरण करते हैं।

शैली एक ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति है कि जिसे पा लेना प्रत्येक शास्त्रव्यसनी का पहिला कार्य है। जिस विषय अथवा जिस ग्रन्थ की शैली हमारे हस्तगत हो जाएगी फिर उस विषय या उस ग्रन्थ का वास्तविक तात्पर्य भी ठीक 2 हमारी समझ में आ जाएगा । शैली को समझे बिना अर्थज्ञ होने का दम भरना वैसी ही विडम्बना है, जैसी कि घोर अन्धकार में तत्तत्पदार्थों को हाथों से टटोल टटोल कर उनके रंग रूप का वर्णन करने में हो सकती है।

क्रमशः ...

ब्रह्मा के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति कैसे हुई

आशुतोष गर्ग

भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। उनके बहुत-से मानस-पुत्र हैं अर्थात ऐसे पुत्र, जिन्हें ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से उत्पन्न किया। हम ब्रह्मा के बहुत-से पुत्रों के नामों से तो परिचित हैं, किंतु अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि ब्रह्मा के पुत्रों के वे नाम क्यों और कैसे रखे गए। इस संबंध में पौराणिक साहित्य में एक अध्याय उपलब्ध है। उसी के आधार पर यहां ब्रह्मा के कुछ पुत्रों के नाम एवं उनकी व्युत्पत्ति के विषय में बताया जा रहा है।

कुछ कल्प व्यतीत होने पर ब्रह्मा सृष्टि-कार्य में संलग्न हो गए। उस समय उनके 'नरद' नामक कंठ प्रदेश से एक मुनि प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें 'नारद' कहा गया। ब्रह्मा का जो पुत्र उनके चेतस

(चित्त) से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने 'प्रचेता' रखा। फिर एक पुत्र ब्रह्मा के दक्षिण पार्श्व से उत्पन्न हुआ, जो सब कर्मों में दक्ष होने के कारण ही 'दक्ष' कहलाया। वेदों में कर्दम शब्द छाया के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो बालक ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुआ, उसका नाम 'कर्दम' पड़ा। इसी तरह 'मरीचि' शब्द वेदों में तेजोभेद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अतः ब्रह्मा का वह पुत्र जो तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, वह 'मरीचि' कहलाया। जिस बालक ने क्रतु (यज्ञ) समूह का संपादन किया, उसे ब्रह्मा का पुत्र होने पर 'क्रतु' नाम दिया गया। ब्रह्मा का मुख उनका प्रधान अंग है। उस अंग से उत्पन्न हुआ बालक 'इर' अर्थात तेजस्वी था, इसलिए वह 'अंगिरा' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

भृगु शब्द का अर्थ अत्यंत तेजस्वी होता है। ब्रह्मा से उत्पन्न जो बालक अत्यंत तेजस्वी था, वह 'भृगु' कहलाया। जो बालक होने पर भी अपने तेज से अरुण वर्ण का हो गया, वह 'अरुण' नाम से विख्यात हुआ। जिसके योगबल से हंस उसके अधीन रहते थे, ब्रह्मा का वह बालक 'हंसी' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

ब्रह्मा का एक पुत्र विधाता को अत्यंत प्रिय था, उसका नाम 'वशिष्ठ' रखा गया। जो बालक सदा तप में लीन और संपूर्ण कर्मों में संयत रहता था, उसका नाम 'यति' पड़ा। वेदों में 'पुल' शब्द तपस्या के लिए आता है और 'ह' स्फुट-अर्थ में प्रयोग होता है। इसलिए जिस बालक में स्फुट रूप से तपस्या लक्षित हुई, उसे 'पुलह' नाम दिया गया। जिसके पूर्वजन्मों के तप समूह रूप में विद्यमान हैं; वह 'पुलस्त्य' के नाम से विख्यात हुआ। 'त्रि' शब्द त्रिगुणमयी प्रकृति को दर्शाता है और 'अ' विष्णु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जिस बालक की उन दोनों में समान भक्ति है, उसे 'अत्रि' कहा गया। मस्तक पर तपस्या के तेज से प्रकट हुई अग्निशिखा जैसी पांच जटाओं वाला बालक 'पंचशिख' कहलाया। जो तपस्या का भार वहन करने में पूर्ण समर्थ था, वह 'वोढु' कहलाया। जिसने दूसरे जन्म में आंतरिक अंधकार से रहित प्रदेश में तप किया था, उस शिशु का नाम 'अपांतरतमा' हुआ। तपस्या में जिसकी स्वाभाविक रुचि थी, वह पुत्र 'रुचि' नाम से प्रसिद्ध हुआ। सहसा ब्रह्मा के क्रोध के समय ग्यारह बालक प्रकट हुए और रोने लगे, वे अपने रोदन के कारण 'रुद्र' कहलाए।

ऐतिहासिक भूल करने जा रहा बांग्लादेश

केएस तोमर

यह विडंबना ही है कि बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सैन्य प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है, जो 1971 के नरसंहार की यादें ताजा करता है। मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना का अत्याचार आज भी बांग्लादेश की सामूहिक स्मृति में अंकित है, जिसमें तीस लाख से ज्यादा लोग मारे गए और अनगिनत लोग विस्थापित हुए थे। इसके बावजूद, उन भयावहताओं के लिए जिम्मेदार मुल्क के साथ सहयोग का यह निर्णय ऐतिहासिक जवाबदेही के क्षरण का संकेत देता है। पाकिस्तान ने उस कृत्य के लिए आज तक माफी नहीं मांगी है, क्षतिपूर्ति करना तो दूर की बात! इस तरह इस्लामाबाद से प्रगाढ़ता बढ़ाकर ढाका अपने नागरिकों को अलग-थलग करने के साथ ही उनके जख्मों को फिर से कुरेद रहा है, जिनके बारे में माना जाता था कि वे भर चुके हैं।

कूटनीतिक मानदंडों से दूर और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को नजर अंदाज कर अंतरिम सरकार का यह निर्णय बांग्लादेश की विदेश नीति में एक हैरतअंगेज और विवादास्पद बदलाव का प्रतीक है, जिसने इतिहासकारों और रणनीतिकारों, दोनों को चकित कर दिया है। इसका कारण भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति को माना जा सकता है, जिसके तहत उसने बेदखल नेता शेख हसीना को संरक्षण दिया, जिनसे उस मुल्क की अन्य राजनीतिक ताकतें अलग-थलग हो गईं। अगले माह पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षक बांग्लादेश की चार छावनियों में काम करेंगे। बांग्लादेश का यह कदम न केवल अपने इतिहास से धोखा है, बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता में बदलाव का परेशान करने वाला संकेत भी है।

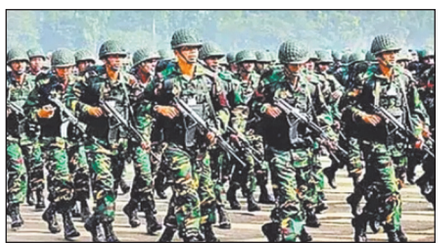

नैतिक और ऐतिहासिक निहितार्थों से परे, यह समझौता विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक परिणाम देने वाला है। मोहम्मद यूनुस के इस्लामाबाद से बेहतर रिश्ते बनाने के प्रयास बांग्लादेश और भारत के मजबूत संबंधों को कमजोर करने का खतरा पैदा करते हैं। नई दिल्ली ने बांग्लादेश के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है, जिसके तहत आर्थिक मदद, बुनियादी सहयोग और आतंकवाद से निपटने से लेकर व्यापार तक के मुद्दों पर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। बांग्लादेशी सेना पर पाकिस्तानी सेना की काली छाया का प्रभाव अपने पूर्वी पड़ोसी देश में स्थिरता बनाए रखने के भारत के प्रयासों के लिए सीधी चुनौती है।

पाकिस्तानी सेना का भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तानी प्रशिक्षकों की बांग्लादेशी सेना तक पहुंच भारत विरोधी विचारधारा की जड़ों को मजबूत करने का काम करेगी। इससे भारत-बांग्लादेश साझा सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। भारत, जो बांग्लादेश को अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत एक प्रमुख सहयोगी मानता है, अब इस नए तालमेल के संभावित नतीजों को कम करते हुए ढाका के प्रति अपने नजरिये को फिर से संतुलित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहा है।

यह निर्णय बांग्लादेश की घरेलू प्राथमिकताओं और उसके नेतृत्व पर भी सवाल उठाता है। भारत के प्रति सकारात्मक रुख रखने वाली पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को बांग्लादेश में आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता का श्रेय दिया जाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसका उद्देश्य भारत पर कथित अति-निर्भरता को संतुलित करना हो सकता है, जबकि अन्य इसे उन मतदाताओं को संतुष्ट करने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जो भारत विरोधी भावनाओं को प्रश्रय देते हैं। इस समझौते के समय से पता चलता है कि राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक विचारों की भी इसमें भूमिका होगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा किए जा रहे पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन से भी विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों ने सरकार पर विपक्षी दृष्टिकोण को मिटाने और पक्षपातपूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है, तो समर्थकों का तर्क है कि इससे समावेशिता सुनिश्चित होती है और ऐतिहासिक विकृतियों को सुधारा जा रहा है। इसके परिणाम गंभीर होंगे, यह युवाओं के मन?को आकार देने, सामाजिक एकजुटता को प्रभावित करने और अकादमिक स्वतंत्रता पर बहस को बढ़ावा?देने का काम करता है। फिर भी, यह रणनीति जोखिमों से भरी है। आर्थिक उथल-पुथल और आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहा पाकिस्तान शायद ही आदर्श साझेदार बन पाए। उसकी सेना मानवाधिकारों के हनन और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोपों से घिरी है। उससे जुड़ना बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल करने के साथ ही चरमपंथ से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है। घरेलू स्तर पर, इस समझौते को नागरिक समाज, बुद्धिजीवियों और आबादी के उन वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो 1971 में पाकिस्तानी नरसंहार से काफी खफा हैं।

भारत के लिए यह घटनाक्रम एक कूटनीतिक दुविधा और बहुत बड़ा सिरदर्द है। सख्त प्रतिक्रिया से ढाका के अलग-थलग पड़ने का खतरा है, जबकि चुप रहने से इस्लामाबाद का मनोबल बढ़ सकता है। ऐसे में सही संतुलन कायम करना नई दिल्ली के लिए अहम होगा, जिसे अब अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ तेजी से जटिल होते संबंधों से निपटना होगा। 1971 के अत्याचारों को भूलना न केवल उन लोगों का अपमान है, जिन्होंने बलिदान दिया, बल्कि उस राष्ट्र के लिए भी एक खतरनाक मिसाल है, जिसकी पहचान उसके मुक्ति संघर्ष से गहराई से जुड़ी हुई है। इस समझौते के निहितार्थ बांग्लादेश से परे हैं, क्योंकि इसे दक्षिण एशिया के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ, बांग्लादेश की पाकिस्तान से दोस्ती को बहुध्रुवीय दुनिया में कई साझेदारियों का लाभ उठाने की एक बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, इसके अपने अंतर्निहित खतरे भी हैं।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई खटास के पीछे हसीना का मामला भी काम कर रहा है। 1975 में जब शेख हसीना के परिजनों की हत्या हुई थी, तब भी भारत ने उन्हें शरण दी थी। हालांकि अभी हसीना को शरण देने से सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और जल-बंटवारे, जैसे मुद्दों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।

आज का इतिहास

1829 अगस्त कलिंगमैन की जोहान वोल्फगैंग वॉन फ़ाउस्ट का ब्राउनश्विक में प्रीमियर किया गया।
1862 अमेरिकी नागरिक युद्ध-अपनी पहली महत्वपूर्ण जीत में, यूनियन फोर्सेज ने आधुनिक नैन्सी, केंटकी के पास मिल स्प्रिंग्स की लड़ाई में संघियों को हराया।
1907 ईरान के विख्यात संगीतकार अमीनुल्ला हुसैन का तुर्कमानिस्तान के एक ईरानी परिवार में जन्म हुआ।
1910 जर्मनी तथा बोलिविया के वाणिज्यिक तथा दोस्ताना समझौता समाप्त हुआ।
1917 लगभग 50 टन टीएनटी पश्चिम हाम के सिल्वर टाउन के एक कारखाने में, वर्तमान में ग्रेटर लंदन में विस्फोट हुआ, जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए।
1920 अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने के खिलाफ मतदान किया।
1921 मध्य अमेरिकी देशों कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरस तथा अल सल्वाडोर ने समझौते पर हस्ताक्षर किये।
1927 ब्रिटेन की सरकार ने अपनी सेना चीन भेजने का निर्णय लिया।
1938 जनरल मोटर्स ने डीजल इंजन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया।
1949 कैरेबियाई देश क्यूबा ने इजरायल को मान्यता दी।
1978 संघीय अपील न्यायालय के न्यायाधीश विलियम एच वेबस्टर एफबीआई निदेशक नियुक्त किए गए।
1983 अमेरिकी सेना के काउंटर इंटेलिजेंस कोर के 32 साल बाद बोलीविया में नाजी एसएस अधिकारी क्लाउस बार्बी को गिरफ्तार किया गया, जिससे उन्हें अर्जेंटीना भागने में मदद मिली।
1990 दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने पर लगे प्रतिबंध की अनदेखी करते हुए इंग्लैंड से 15 क्रिकेटरों का एक दल दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जोहानेसबर्ग पहुंचा।
1992 सिटी ऑफ़ एंजल्स वर्जीनिया थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में बंद हुआ। इसने 878 प्रदर्शन किए हैं।

त्रिवेणी तट पर सजा धर्म, संस्कृति, आस्था, आध्यात्म, व आधुनिकता का अद्भुत संगम

दीपक कुमार त्यागी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की दिव्य धरती पर धर्म-संस्कृति व प्राचीन परंपराओं के अद्भुत संगम से परिपूर्ण दिव्य शहर गंगा यमुना व सरस्वती के संगम तट की रेती पर अब अपना स्वरूप पूरी तरह से ले चुका है। अपनी भव्यता के चलते ही आस्था, धर्म, आध्यात्म व संस्कृति के विशाल संगम का महाकुंभ शुरू होने से पहले ही जबरदस्त चर्चा में आ चुका है। क्योंकि संगम तट पर आधुनिक व प्राचीन के अद्भुत संगम की आस्था और अध्यात्म एक पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अपनी थीम के ही अनुरूप भव्य-दिव्य व नव्य आकार ले चुकी है। दिन-रात की मेहनत के बाद अब संगम तट की रेती पर बसी एक बड़ी अद्भुत भव्य अनोखी नगरी महाकुंभ के आयोजन के साक्षी बनने आ रहे संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं व पर्यटकों का दिल खोलकर के स्वागत करने के लिए तैयार हो गयी है। संगम तट की पूजनीय दिव्य धरा पर संत, महात्माओं, श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए एक ऐसा भव्य शहर तैयार हो चुका है, जिसको शिल्पकारों ने इस तरह से तराशा है कि धार्मिक आस्था व प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ भौतिक सुख साधनों की कामना रखने वाले लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं, जिसकी भव्यता देखकर के देखने वाले की आंखें चौंधिया जायेंगी।

हालांकि इस प्राचीन धर्म नगरी प्रयागराज में वर्ष 2019 के कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ही भव्य-दिव्य आयोजन 3200 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में हुआ था। लेकिन वर्ष 2025 में एकबार फिर से महाकुंभ की यह दिव्य नगरी मोदी-योगी के कुशल मार्गदर्शन में एक नया इतिहास रचने जा रही है। जिसके चलते ही इस बार महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ के दृष्टिकोण से कुंभ के मेला क्षेत्र का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। लंबे समय से चली आ रही तैयारियों के बाद अब वह समय आ गया है जब त्रिवेणी के अद्भुत दिव्य तट पर सनातन धर्म के अनुयायियों का धर्म, आध्यात्म व आस्था के संगम के महाकुंभ का विशाल आयोजन 13 जनवरी शुरू होने वाला है और जोकि 26 फ़रवरी तक चलेगा। जिसको अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य व नव्य स्वरूप प्रदान करने को मोदी व योगी सरकार दृढ़ संकल्पित है।

इस बार के महाकुंभ 2025 के आयोजन के बजट पर एक नज़र डालें तो महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 7,500 करोड़ रुपए का खर्च सामने आ रहा है। जिस में से 2,100 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा किया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,435.68 करोड़ रुपए का विशाल बजट निर्धारित किया है। जबकि वर्ष 2019 में कुंभ मेले के लिए 4,200 करोड़ रुपए का बजट था। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो हर कुंभ मेले की तरह ही इस बार भी महाकुंभ का देश की जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहने की संभावना है, जिसके चलते ही मेला क्षेत्र छोटे व बड़े व्यापारियों, दुकानदारों आदि को आकर्षित करने का कार्य बखूबी कर रहा है, लोग महाकुंभ क्षेत्र में तरह-तरह का व्यापार करने के लिए उत्साहित हैं।

हालांकि सनातन धर्म संस्कृति व परंपराओं के अनुसार महाकुंभ का यह पूरा समय ही अनुष्ठानों का एक भव्य दिव्य समागम है। जिसमें पूरे समय ही पूजा पाठ व स्नान आदि मुख्य रूप से होता है, लेकिन इस मेले में कुछ

विशेष तिथि पर स्नान करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। जिसमें भाग लेने के लिए ही संगम के किनारे करोड़ों संत, महात्मा व तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं और उन सभी का अटूट, श्रद्धा व विश्वास होता है कि शाही स्नान के लिए तय तिथियों में संगम के पवित्र जल में स्नान करने से उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वयं खुद के साथ-साथ अपने पूर्वजों को भी पुनर्जन्म के जीवन चक्र से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए शाही स्नान की तिथि पर कुंभ नगरी में भारी भीड़ रहती है। इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की वह विशेष तिथियां हैं -

पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। बसंत पंचमी 03 फ़रवरी 2025। माघी पूर्णिमा 12 फ़रवरी 2025। महा शिवरात्रि 26 फ़रवरी 2025 हैं, जिन पर स्नान करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों के दिव्य भव्य व नव्य महाकुंभ की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सरकार ने महाकुंभ-2025 को भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप प्रदान करते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का कार्य किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे महाकुंभ स्थल को एक जनपद का दर्जा दिया गया है और वहां पर जनपद स्तरीय अधिकारियों की पूरी टीम तैनात की गयी है। एक जनपद की तरह ही जरूरी विभिन्न विभागों के कार्यालय सर्किट हाउस और पुलिस लाइन का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की उम्मीद को देखते हुए इस बार कुंभ क्षेत्र का विस्तार 4000 हेक्टेयर में किया गया है, भारी भीड़ के मद्देनजर महाकुंभ की बसावट में बदलाव किया गया है। इस बार 25 सेक्टर में महाकुंभ नगरी को बसाया गया है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए गंगा पर 30 पोंटून पुल बनाये गये हैं।

महाकुंभ में %स्वच्छ भारत मिशन% को अमली जामा पहनाने के लिए स्वच्छता का माडल प्रस्तुत होगा। योगी सरकार ने महाकुंभ को स्वच्छता के माडल के रूप में देश व दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए पूरी तैयारी की है। योगी सरकार ने स्वच्छ महाकुंभ के मद्देनजर इस बार 1.5 लाख शौचालय बनाये हैं, मेला क्षेत्र में 25 हज़ार कूड़ेदान लगाए गए हैं, 15 हज़ार स्वच्छता कर्मी तैनात किए हैं, 160 अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों का इंतजाम किया है।

महाकुंभ को दिव्य व भव्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिर एवं घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है, 29 मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है, 11 कॉरिडोर का विकास किया गया है, 12 किमी अस्थायी घाट का निर्माण किया गया है, 8 किमी रिवर फ्रंट सड़कें बनाई गयी हैं।

महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सबसे बड़ा अस्थायी शहर बनाया गया है, 1.5 लाख टेंट लगाये गये हैं, 69 हज़ार एलईडी लाइटिंग और सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटिंग लगायी गयी हैं। 400 किलोमीटर से अधिक की अस्थायी सड़कें और चेक-ओर्ड प्लेट शीट बनायी गयी हैं। महाकुंभ की तैयारियों के लिए प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार किया गया है। 1800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पार्किंग विकसित की गयी है, 201 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया, 40 जंक्शनों और 48 सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया, 14 आरओबी और फ्लाईओवर का विकास किया गया है। डिजिटल कुंभ के लिए 1.5 लाख टेंट और शौचालयों की निगरानी की जा रही है, 2600 से अधिक भीड़ निगरानी सेटअप कैमरे जगह-जगह लगाए गए हैं, 24×7 आईसीसीसी निगरानी रहेगी, 10 डिजिटल खोया-पाया केंद्र बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में महाकुंभ की इन विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तैयारियों के दम पर ही कहा जा सकता है कि इस बार 13 जनवरी से 26 फ़रवरी तक चलने वाले महाकुंभ के मेले मे त्रिवेणी संगम तट और गंगा, यमुना, सरस्वती मिलन के स्थल पर संत, महात्मा, श्रद्धालु व पर्यटक भारी संख्या में आकर के सुलभता के साथ स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे और देश व प्रदेश की जीडीपी में अपना योगदान देंगे।

भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है सेना

योगेश कुमार गोयल

थलसेना के अदम्य साहस, जांबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और उनकी शहादत को याद करते हुए 15 जनवरी को हम 77वां भारतीय सेना दिवस मना रहे हैं। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है 'स्वयं से पहले सेवा'। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को ही यह दिवस मनाए जाने का विशेष कारण यह है कि आज ही के दिन 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर-इन-चीफ बने थे। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। जनरल फ्रांसिस बुचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ थे। करियप्पा को ही भारत-पाक आजादी के समय दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1947 में उन्होंने भारत-पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा (म्यांमार) में जापानियों को शिकस्त देने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' दिया गया था। 1953 में वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और 94 वर्ष की आयु में 1993 में उनका निधन हुआ। 77वें सेना दिवस समारोह की थीम है 'समर्थ भारत, सक्षम सेना' और इस बार का फोकस सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। सेना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली परेड में इस बार के-9 वज्र स्व-चालित हॉवित्जर तोपें, पैदल सेना लड़ाकू वाहन बीएमपी-2 सरथ, टी-90 टैंक, स्वाति हथियार लोकेटिंग रडार, सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, मल्टी-बैरल रॉकेट सिस्टम, एटोर एन1200 ऑल-टेरेन वाहन, ड्रोन जैमर सिस्टम, मोबाइल संचार नोड्स इत्यादि प्रदर्शित किए जाएंगे। परेड में पहली बार 12 रोबोटिक खच्चर भी हिस्सा लेंगे। सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का प्रतिनिधित्व करते इन रोबोटिक खच्चरों को पिछले साल सेना में शामिल किया गया था, जो दुर्गम इलाकों में आसानी से चलते हुए न केवल भार ढो सकते हैं बल्कि दुश्मनों से भी निपट सकते हैं। भारतीय सेना की ताकत निरंतर बढ़ रही है और सेना की इस बढ़ती ताकत का श्रेय आधुनिक तकनीक, उन्नत हथियार प्रणाली तथा सैनिकों के प्रशिक्षण में निरंतर सुधार को दिया जा सकता है। चूंकि दुनिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर चुकी है, इसलिए थलसेना भी लगातार अपने हथियारों तथा उपकरणों को आधुनिक कर रही है और ऐसी योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, जिससे सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी व्यापक उपयोग किया जा सके। पिछले एक दशक में थलसेना ने 'मेक इन इंडिया' के तहत विज्ञान और तकनीकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। चूंकि दुनिया में युद्ध के तौर-तरीके लगातार बदल रहे हैं, इसीलिए भविष्य की संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना कई तरह के प्रशिक्षण और नए हथियारों के साथ स्वयं को अपडेट कर रही है। हाल के वैश्विक संघर्षों ने स्वदेशी युद्धक्षेत्र समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सदाचार का ताबीज बांध चलेगी महाराष्ट्र सरकार?

अमिताभ श्रीवास्तव

बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मुंबई आए थे। एक आयोजन बंद दरवाजे के भीतर हुआ, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने वाले सत्ताधारी पाले के विधायकों के लिए था। हालांकि इसकी आवाज के निकलने पर रोक लगी थी, लेकिन उपस्थिति से लेकर प्रधानमंत्री के सुझाव और चिंताएं सभी बाहर तक सुनाई दे गईं। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी ही पार्टी के नाराज चल रहे नेता छगन भुजबल की अनुपस्थिति खबरें बनने का अवसर दे गई। आम तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मंत्रिपरिषद और नए सांसदों के साथ हमेशा ही संवाद करते आए हैं, किंतु इस बार महाराष्ट्र के सत्ताधारी दलों के विधायकों से उन्होंने अपने मन की बात करने की कोशिश की।

राज्य की नई सरकार में यदि मुख्यमंत्री के बदले चेहरे को छोड़ दिया जाए तो एक उपमुख्यमंत्री समेत अनेक मंत्री ऐसे हैं, जो दोबारा अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुराने विधायकों की वापसी हुई है। फिर भी पहली बार विधानमंडल की चौखट पर पहुंचने वाले भी कम नहीं हैं। ऐसे में इतिहास और वर्तमान के कार्यकलापों के बहाने समझने और समझाने की कहीं अवश्य ही आवश्यकता अनुभव हुई होगी। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिलने पर शिवसेना ने कांग्रेस और राकांपा के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार का गठन किया। कोरोना महामारी के बीच आघाड़ी को अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा। मंत्री संजय राठौड़ को एक युवती के आरोपों के चलते अपने पद का त्याग करना पड़ा। इन्हीं के साथ माफिया गिरोह से जमीन का सौदा करने के आरोप में मंत्री नवाब मलिक को जेल की हवा खानी पड़ी। इनके अलावा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री छगन भुजबल निशाने पर रहे।

ढाई साल बाद शिवसेना के टूटने पर महागठबंधन की सरकार बनी और संजय राठौड़ दोबारा मंत्री बन गए। बाद में राकांपा में फूट के बाद अजित पवार और छगन भुजबल

भी महागठबंधन सरकार के पद पाकर दोबारा सत्तासीन हो गए। अब वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन पर पूर्व मंत्री भुजबल और अब्दुल सत्तार को छोड़कर लगभग सभी को दोबारा मंत्री बनने का अवसर मिल गया है। यहां तक कि कुछ को पुराने विभाग भी मिल गए हैं। इस स्थिति में स्वच्छ छवि के साथ पांच साल सरकार चलाना बड़ी चुनौती है।

महाविकास आघाड़ी ने सत्ता गंवाने के बाद अगले ढाई साल महागठबंधन के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनके समक्ष पांच साल का नया अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी की सत्ताधारी मंत्रियों-विधायकों की चर्चा में आम जनता के प्रति संवेदनशीलता, सांकेतिक रूप में भ्रष्टाचार की आशंका वाले कामों से किनारा और स्वास्थ्य-परिवार की चिंता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। आम जन के बीच जनप्रतिनिधि का होना हर तरह से सरकार व संगठन दोनों को मजबूती प्रदान करता है। भ्रष्टाचार छवि खराब करता है और नाराजगी पैदा करता है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार का ध्यान इसलिए भी आवश्यक है कि राज्य ने अनेक प्रमुख नेता जैसे विलासराव देशमुख, आरआर पाटील, जयदीप सातव, विमल मुंदड़ा आदि को गंवाया है। सार्वजनिक जीवन में स्वास्थ्य और परिवार की चिंता से दूरी बढ़ने से परेशानियां पैदा होती हैं, जिनके कई बार घातक परिणाम भी सामने आते हैं।

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रदीर्घ राजनीतिक अनुभव से नए राजनीतिज्ञों को सलाह-मशविरा दिया करते हैं। इस बार महाराष्ट्र में चूंकि बड़े बहुमत के साथ सरकार का गठन हुआ है, इसलिए कुछ चिंताओं और सावधानियों के नीचे रेखा खींचना आवश्यक हो चला था। राज्य में भाजपा ने भले ही 132 विधायकों की जीत के साथ सरकार बनाई हो, लेकिन उसके साथी शिवसेना(शिंदे गुट) 59 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(अजित पवार गुट) 41 सीटों के साथ उसके साथ सत्ता के भागीदार हैं। यदि भाजपा अपने विधायकों और मंत्रियों पर नियंत्रण रख सकती है तो उसे दूसरे दलों के विधायकों और मंत्रियों की छवि पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यह बात कहना राज्य के स्तर पर संभव नहीं थी तो केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री के आगमन के बहाने बता दी गई। आरंभ में ही सरकार के साथ चलने और स्वच्छ छवि बनाए रखने के लिए सदाचार का ताबीज पहना दिया गया। अब यह कितने दिन काम करेगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। किंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर ताबीज के हाल पर नजर रखने की नैतिक जिम्मेदारी अवश्य ही होगी। तीसरी बार महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री फडणवीस के कंधों पर है। पहले पांच साल उनकी स्वच्छ छवि के प्रमाण हैं। बीच के तीन दिन की सरकार को छोड़ दिया जाए तो अगली चुनौती सामने है।

वर्ष 2014 में शिवसेना के गठबंधन में सरकार किसी गंभीर लांछन की शिकार नहीं हुई थी। हालांकि उस दौरान भाजपा के 122 विधायकों के मुकाबले शिवसेना के विधायक 63 ही थे। इस बार भाजपा के 132 विधायकों की तुलना में शिवसेना के शिंदे गुट और राकांपा(अजित पवार गुट) के मिलाकर सौ विधायक हैं।

सभी को साथ लेकर चलना संघर्षपूर्ण कार्य है। वह भी उस दौर में जब कुछ पार्टी के नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया है। दूसरी तरफ सत्ताधारियों का विधानसभा में बड़ा बहुमत सिर चढ़ कर बोल रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच राज्य के विधायकों के लिए सही संदेश तो दे ही गए हैं, जो जनभावना-आवश्यकता से जुड़ा है। चूंकि अतीत के अनुभव अच्छे नहीं हैं, इसलिए उचित समय में उचित संदेश का मिलना भविष्य के लिए अच्छा है। आगे मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे रेखांकित बातों पर कितना अमल करवा पाते हैं। मगर यह तय है कि आने वाले पांच सालों में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी इस बात पर नजर जरूर रहेगी कि महाराष्ट्र में उनका सदाचार का ताबीज कितना असरकारक रहा।

9 ए कोटला मार्ग कांग्रेस के लिए नया अध्याय लिखेगा

नीरज कुमार दुबे

हम आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का मुख्यालय '7 जंतर-मंतर रोड' हुआ करता था लेकिन आपातकाल के बाद की चुनावी हार और फिर कांग्रेस के विभाजन के बाद बदली परिस्थितियों के बीच 1978 में यह पता बदल गया।

दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित '24 अकबर रोड' की पहचान बीते करीब पांच दशकों से भले ही कांग्रेस के मुख्यालय की है, लेकिन यह पता कई ऐसे फैसलों, नीतियों और घटनाओं का गवाह है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ भारत के लिए भी परिवर्तनकारी एवं ऐतिहासिक साबित हुए। इस पते ने इंदिरा गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे तक सात कांग्रेस अध्यक्ष देखे। यह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की दुखद हत्या, सीताराम केसरी की अध्यक्ष पद से विदाई, 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी, 1984 की प्रचंड जनादेश वाली जीत, 1991, 2004 और 2009 की गठबंधन वाली सरकार, 2014 और 2019 की करारी हार तथा 2024 की हार में भी भविष्य की उम्मीद समेत कई उतार-चढ़ाव वाले ऐतिहासिक पलों का साक्षी है। अब कांग्रेस ने आज से 24 अकबर रोड़ से कुछ किलोमीटर दूर '9ए कोटला' मार्ग पर अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर लिया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह '24 अकबर रोड' को खाली नहीं करेगी।

हम आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद से कांग्रेस का मुख्यालय '7 जंतर-मंतर रोड' हुआ करता था लेकिन आपातकाल के बाद की चुनावी हार और फिर कांग्रेस के विभाजन के बाद बदली परिस्थितियों के बीच 1978 में यह पता बदल गया। उस समय मुश्किल दौर का सामना कर रहीं इंदिरा गांधी को उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस (आई) के राज्यसभा सदस्य जी. वेंकटस्वामी ने अपने आधिकारिक निवास '24, अकबर रोड' को पार्टी के कामकाज के लिए दे

दिया। इसके बाद से लुटियंस जोन में सफेद रंग का यह बंगला कांग्रेस मुख्यालय बन गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि '24 अकबर रोड' पर कांग्रेस ने 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सत्ता में वापसी की। वर्ष 1984 में उनकी हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 400 से अधिक सीटें जीतीं थीं। इसके बाद के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सत्ता से विदाई हो गई।

वर्ष 1991 के चुनाव से पहले राजीव गांधी की हत्या हो गई, हालांकि पार्टी ने गठबंधन की बदौलत सत्ता में वापसी की और फिर '24 अकबर रोड' पर पी वी नरसिम्हा राव के वर्चस्व का दौर शुरू हुआ। इसके कुछ साल बाद सीताराम केसरी अध्यक्ष बने, हालांकि 'मंडल' और 'कमंडल' के प्रभुत्व वाली राजनीति के उस दौर में कांग्रेस का ग्राफ नीचे की ओर जाने लगा। फिर कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग तेज होने लगी। इसके बाद, वर्ष 1998 में सोनिया गांधी की सक्रिय राजनीतिक पारी की शुरू हुई और केसरी की '24 अकबर रोड' से विदाई हुई। कांग्रेस के विरोधी यह आरोप भी लगाते हैं कि केसरी के साथ पार्टी मुख्यालय में अपमानजनक व्यवहार किया गया। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद '24 अकबर रोड' की धमक फिर से बढ़ने लगी और कांग्रेस का ग्राफ भी तेजी से उठने लगा। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बावजूद पार्टी ने 2004 के चुनाव में शानदार वापसी की और उसके नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार बनी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ और बढ़ा तथा उसने खुद की 200 से अधिक सीटों और गठबंधन के सहयोगियों की बदौलत सत्ता बरकरार रखी।

वर्ष 2014 में कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर शुरू हुआ और उस चुनाव में पार्टी अपने इतिहास में 44 सीटों के सबसे न्यूनतम आंकड़े पर सिमट गई। इसके अगले चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हुई और उसे मात्र 52 सीटें मिलीं। इस मुख्यालय पर कांग्रेस का आखिरी लोकसभा चुनाव 2024 का रहा जिसमें पार्टी की हार हुई, लेकिन उसने 99 सीटें हासिल कीं और यह उम्मीद पैदा हुई कि भारतीय राजनीति में वह अपना पुराना गौरव फिर से हासिल कर सकती है। कांग्रेस का मुख्यालय '24 अकबर रोड' पर रहते हुए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी की कमान संभाली। कांग्रेस मुख्यालय बनने से पहले इस इमारत में 1961 से दो साल तक म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता और नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं आंग सान सू की यहां रही थीं। सू की उस समय करीब 15 साल की थीं और अपनी राजनयिक मां के साथ यहां आई थीं। उस समय '24 अकबर रोड' को 'बर्मा हाउस' के नाम से जाना जाता था। वैसे, इस भवन का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत में एडविन लुटियंस ने 1911 और 1925 के बीच करवाया था। अब कांग्रेस का जो नया मुख्यालय बना है उसको लगभग 242 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इंदिरा गांधी भवन को पार्टी और नेताओं की आवश्यकताओं के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस मुख्यालय में प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक गतिविधियों का ठीक से संचालन करने के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। इस भवन का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। इंदिरा भवान में आधुनिक सुविधाओं और टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग का विशेष ध्यान रखा गया है।

सिर्फ औपचारिकता नहीं है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण

विवेक शुक्ला

भारत के मित्र देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करना भारत और उस देश के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है।

यह दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का एक अवसर है। कुछ मामलों में, यह निमंत्रण रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंधों को गहरा करने का एक तरीका है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां साझा हित हैं। गणतंत्र दिवस एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां भारत अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ सकता है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रख सकता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि गणतंत्र दिवस भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने का एक मंच है। एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की उपस्थिति इस अवसर को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देती है।

एक बात और कि यह कभी-कभी एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष देश को आमंत्रित करना उस देश के प्रति भारत के समर्थन या प्रशंसा का संकेत हो सकता है। महत्वपूर्ण यह

भी है कि कभी-कभी किसी विशिष्ट वर्षगांठ या घटनाक्रम को चिह्नित करने के लिए एक विशेष राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है।

संयोग से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। वे भारत के मित्र होने के साथ-साथ एक करिश्माई नेता थे, जिन्होंने इंडोनेशिया को डच औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक प्रभावशाली वक्ता और राष्ट्रवादी नेता थे। भारत सरकार ने उन्हें बहुत सोच-विचार करने के बाद देश के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया था। सुकर्णो भारत के एक बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। उनके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक और कई अन्य नेताओं से गहरे संबंध थे। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजधानी के नेशनल स्टेडियम (अब ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम) में आयोजित किया गया था। पहले और 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों का एक स्पष्ट प्रमाण है।

तुलसी की खेती

कर्पूर तुलसी
काली तुलसी
वन तुलसी या राम तुलसी
जंगली तुलसी
होली बेसिल

श्री तुलसी या श्यामा तुलसी

तुलसी अत्यधिक औषधीय उपयोग का पौधा है। जिसकी महत्ता पुरानी चिकित्सा पद्धति एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति दोनों में है। वर्तमान में इससे अनेकों खाँसी की दवाएँ साबुन, हेयर शैम्पू आदि बनाए जाते लगे हैं। जिससे तुलसी के उत्पाद की मांग काफी बढ़ गई है। अत- मांग की पूर्ति बिना खेती के संभव नहीं हैं।

मृदा व जलवायु

इसकी खेती, कम उपजाऊ जमीन जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो, अच्छी होती है बलूई दोमट जमीन इसके लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। इसके लिए उष्ण कटिबंध एवं कटिबंधीय दोनों तरह जलवायु होती है।

भूमि की तैयारी

जमीन की तैयारी ठीक तरह से कर लेनी चाहिए। जमीन जों के दूसरे सप्ताह तक तैयार हो जानी चाहिए।

बुवाई / रोपाई

इसकी खेती बीज द्वारा होती है लेकिन खेती में बीज की बुवाई सीधे नहीं करनी चाहिए। पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। बाद में उसकी रोपाई करनी चाहिए।

पौध तैयार करना

जमीन की 15 - 20 सेमी. गहरी खुदाई कर के खरपतवार आदि निकाल तैयार करा लेना चाहिए। 15 टन प्रति हे. की दर से गोबर की सड़ी खाद अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। 1 मी. ङ्क 1 मी. आकार की जमीन सतह से उभरी हुई क्यारियां बना कर उचित मात्र में कंपोस्ट एवं उर्वरक मिला दिन चाहिए। 750 ग्रा. - 1 किग्रा. बीज एक हेक्टयेर के लिए पर्याप्त होता है। बीज की बुवाई 1ः10 के अनुपात में रेत या बालू मिला कर 8-10 सेमी. की दूरी पर पक्तियां में करनी चाहिए। बीज की गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए। जमाव के 15-20 दिन बाद 20 कि./ हे. की दर से नेत्रजन डालना उपयोगी होता है। पांच- छह सप्ताह में पौध रोपाई हेतु तैयार हो जाती है।

रोपाई

सूखे मौसम में रोपाई हमेशा दोपहर के बाद करनी चाहिए। रोपाई के बाद खेत को सिंचाई तुरंत कर देनी चाहिए। बादल या हल्की वर्षा वाले दिन इसकी रोपाई के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इसकी रोपाई लाइन में लाइन 60 से. मी. तथा पौधे से पौधे 30 से. मी. की दूरी पर करनी चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण

इसकी पहली निराई गुड़ाई रोपाई के एक माह बाद करनी चाहिए। दूसरी निराई - गुड़ाई पहली निराई के 3-4 सप्ताह बाद करनी चाहिए। बड़े क्षेत्रों में गुड़ाई ट्रैक्टर से की जा सकती है।

उर्वरक

इसके लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद जमीन में डालना चाहिए। इसके अलावा 75-80 किग्रा. नेत्रजन 40-40 किग्रा. फास्फोरस व पोटाश की आवश्यता होती है। रोपाई के पहले एक तिहाई नेत्रजन तथा फस्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में डालकर जमीन में मिला देने चाहिए। शेष नेत्रजन की मात्रा दो बार में खड़ी फसल में डालना चाहिए।

कटाई

जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाए तथा नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगे तो इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। रोपाई के 10-12 सप्ताह के बाद यह कटाई के लिए तैयार हो जाती है।

आसवन

तुलसी का तेल पूरे पौधे के आसवन से प्राप्त होता है। इसका आसवन, जल तथा वाष्प, आसवन, दोनों विधि से किया जा सकता है। लेकिन वाष्प आसवन सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। कटाई के बाद तुलसी के पौधे को 4-5 घंटे छोड़ देना चाहिए। इससे आसवन में सुविधा होती है।

आय - व्यय विवरण

प्रति हेक्टेयर व्यय - रू. 10,500
तेल का पैदावार - 85 किलो प्रति हेक्टेयर
टेल की कीमत - 450 - रूपया प्रति किलो - 8/5 ङ्क 450 = 38,250
शुद्ध लाभ : रू. 38, 250 - 10,500 = 27,750

पैदावार

इसके फसल की औसत पैदावार 20 - 25 टन प्रति हेक्टेयर तथा तेल का पैदावार 80- 100 किग्रा. हेक्टेयर तक होता है।

परिचय

तुलसी की ओसिमम प्रजाति को तेल उत्पादन के लिए उगाया जाता है। तुलसी की इस प्रजाति की भारत में बड़े पैमाने पर खेती होती है। उत्तर प्रदेश में बरेली, बादयूं, मुरादाबाद और सीतापुर जिलों में तथा बिहार के मुंगेर जिला में इसकी खेती की जाती है। इसका प्रयोग परफ्यूम व कास्मेटिक इंडस्ट्रीज में अधिक होता है। तूलसी की ओसीमस सेंक्टेम प्रजाति के सारभूत तेल की अधिक कीमत होती है, किन्तु तेल की मात्रा कम मिलती है।

तुलसी की विभिन्न प्रजतियां

भारत में तुलसी का पौधा धार्मिक एवं औषधीय महत्व का है। इसे हिंदी में तुलसी, संस्कृत में सुलभा, ग्राम्या, बहूभंजरी एवं अंग्रेजी में होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। लेमिएसी कूल के इस पौधे की विश्व में 150 से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसकी मूल प्रकृति एवं गुण एक समान हैं।

प्रमुख प्रजातियाँ निम्न प्रकार हैं

बेसिल तुलसी या फ्रेंच बेसिल

डाउनलोड करें किसान समाधान एंड्राइड एप्प और जाने अन्य व्यापारिक फसलों की जानकारी

स्वीट फ्रेंच बेसिल या बोबई तुलसी

गुडमार औषधीय पौधे की खेती

गुडमार की खेती

विश्व में पाये जाने वाले अनेकों बहुमूल्य औषधीय पौधों में गुडमार एक बहुउपयोगी औषधीय पौधा है। यह एस्कलपिडेसी कुल का सदस्य है। इसका वानस्पतिक नाम जिमनिमा सिलवेस्ट्री है। गुडमार के पत्ते तथा जड़ औषधीय रूप में उपयोग किये जाते हैं।

वानस्पतिक विवरण

गुडमार बहुवर्षीय लता है। गुडमार की शाखाओं पर सूक्ष्म रोयें पाये जाते हैं। पत्ते अभिमुखी मृदुरोमेश अग्रभाग की तरफ नोकदार होते हैं। एस पर पीले रंग के गुच्छेनुमा फूल अगस्त - सितम्बर माह में खिलते हैं। गुडमार के फल लगभग 2 इंच लम्बे एवं कठोर होते हैं तथा बीज छोटे एवं काले - भूरे रंग के होते हैं।

भौगोलिक वितरण

यह भारत वर्ष के विभिन्न भागों जैसे - मध्य भारत, पशिचमी घाट, कोकण, त्रवनकोर क्षेत्र के वनों में पाया जाता हैं। गुडमार मध्य प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से काष्ठीय रोयेंदार लता के रूप में पाये जाने वाली वनस्पति हैं।

औषधीय उपयोग

गुडमार की पत्तियों का उपयोग मुख्यत- मधुमेह - नियंत्रण औषधीयों के निर्माण में किया जाता है। इसके सेवन से रक्तगत शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, साथ ही पेशाब में शर्करा का आना स्वत- बंद हो जाता है। सर्पविष में गुडमार की जड़ को पीसकर या काढ़ा पिलाने से लाभ होता है। पत्ती या छाल का रस पेट के कीड़े मारने में उपयोग करते हैं। गुडमार यकृत को उत्तेजित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से अग्नाशय की इन्सुलिन स्राव करने वाली ग्रंथियों की सहायता करता है। जड़ों का उपयोग खांसी, हृदय रोग, पुराने ज्वार, वात रोग तथा सफ़ेद दाग के उपचार हेतु किया जाता है।

रासायनिक संगठन

पत्तियों में जिम्नेमिक अम्ल, फ्वेरसियल, एन्थ्रान्वोनोन, जिम्नोसाइडस, सेपोनिन तथा कैल्सियम आक्जेलेट रसायन पाये जाते हैं।

भूमि

गुडमार की खेती के लिए उचित जल निकास वाली दोमट मिटटी अच्छी होती है। गर्मियों में दो बार आड़ी - खड़ी जुताई कर एवं पाटा चलाकर खेत तैयार कर लेना चाहिए। पाटा चलाकर मिटटी को भुरभुरी व समतल कर लेना चाहिए।

बीज

बीजों से खेती करने के लिए रोपनी में पौधा तैयार करना चाहिए। बीज बोने से पूर्व 3 ग्राम डायथेन एम 45 या बावेस्टीन नामक फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित करना चाहिए। उपचारित बीजों को पहले से भरी पालीथीन की थैलियों में बो देना चाहिए। बीजों को बोने व रोपणी बनाने का सही समय अप्रैल - मई माह होता है। माह जुलाई - अगस्त तक पौधे खेत में रोपित करने योग हो जाते है।

कलम द्वारा पौध बनाकर

गुडमार की खेती पुराने पौधों की कलम से पौध बनाकर भी की जा सकती है। इसके लिए जनवरी - फ़रवरी माह उत्तम होता है। पालीथीन बैग में पौध तैयार कर जुलाई - अगस्त माह में खेत में रोपित किया जा सकता है। गुडमार एक बहुवर्षीय लता है। यह लगभग 20 - 30 वर्षों तक उपज देती रहती है।

रोपण

रोपण हेतु 1 म 1 मी. की दुरी पर तैयार किये गये गड्ढों में बारिश प्रारम्भ होने के पश्चात् जुलाई - अगस्त माह में रोपित कर दिए जाते हैं प्रति गड्ढा 5 किलोग्राम गोबर की पक्की खाद एवं 50 ग्राम नीम की खली डालनी चाहिए। गुडमार की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 पौधों की आवश्यकता होती है।

आरोहन व्यवस्था

गुडमार एक लता है। आरोहन व्यवस्था के लिए बांस, लोहे के एंगल एवं तारों का उपयोग करना चाहिए।

सिंचाई

गर्मी के समय 10 15 दिन तथा सर्दियों में 20 - 25 दिन के अंतराल में एक बार सिंचाई की जाय तो इसकी बढवार के लिए काफी अच्छा रहता है।

फसल सुरक्षा

कभी - कभी अधिक बारिश के कारण पौधों में पीलेपन की समस्या आती है। इसके लिए बोनी के समय 10 कि.ग्रा. फ़र्स सल्फेट का प्रयोग प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाना चाहिए।

फसल कटाई

गुडमार की खेती मुख्य रूप से इसकी पत्तियों के लिए की जाती है। रोपण के प्रथम वर्ष से ही पत्ते प्राप्त होना प्रारम्भ हो जाते हैं। समय बढ़ने के साथ - साथ इसकी लताए बढती रहती हैं तथा फसल की उपज भी बढती जाती है। गुडमार की फसल एक बार लगाने के बाद लगभग 20 - 25 वर्षों तक फसल देती रहती है। सिंचित अवस्था में दो बार पत्तों की तुड़ाई की जा सकती है।

पहली सितम्बर - अक्तूबर में तथा दूसरी अप्रैल - मई में 7 गुडमार की परिपक्व एवं चयनित पत्तियों को तोड़कर उन्हें छायादार स्थान में सुखाना चाहिए। ग्रीष्म ऋतू में पौधों की परिपक फलियाँ एकत्र कर सुखाई जाती है। फलियों को एकत्र करते समय ध्यान रखना चाहिए की फलियाँ चटक न गई हो अन्यथा बीज उड़ जायेंगे, क्योंकि इनपर रुई लगी रहती है। एस प्रकार प्रति वर्ष पत्तियों को दो बार तुड़ाई करने पर तीसरे वर्ष से प्रत्येक पौधे से लगभग 5 कि.ग्रा. गीली पत्तियां अथवा एक किलोग्राम सुखी पत्तियां प्राप्त होती है। एक हेक्टेयर में लगभग 4 - 6 क्विंटल सुखी पत्तियां प्राप्त होती है।

संग्रहण काल

माह दिसम्बर - जनवरी में गुडमार की पत्तियों को चुनकर एकत्र करना चाहिए एवं इनकी जड़ों को ग्रीष्म ऋतू में उखड़ना चाहिए।

विनाश विहीन विदोहन प्रक्रिया

माह दिसम्बर - जनवरी में इसके पत्तों को हाथ से चुनकर एकत्र करना चाहिए। पत्तियां एकत्र करने के लिए पौधे को नहीं काटना चाहिए।

कुल प्राप्तियां

गुडमार की खेती से किसान 25 से 30 हजार रु, प्रति हेक्टेयर आय अर्जित कर सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल पटना पहुंचते ही तेजस्वी से मिलने होटल मौर्या पहुंचे

पटना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को एकदिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही राहुल गांधी होटल मौर्या पहुंचे जहां राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली थी। राहुल गांधी ने यहां तेजस्वी यादव से मुलाकात की। एक कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। एक तरफ आरजेडी की बैठक तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तेजस्वी से हुई मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गरमायी हुई है। राहुल गांधी तय कार्यक्रम के तहत शनिवार को पटना पहुंचे।पटना पहुंचने पर बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत किया। लेकिन उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव आया। राहुल गांधी पहले एयरपोर्ट से सीधे बापू सभागार जाने वाले थे। जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन में संवाद कार्यक्रम आयोजित है। उसके बाद सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्हें संबोधित करना था।

किराएदारों को मिलेगी फ्री बिजली और पानी : केजरीवाल

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी की योजना का लाभ देने के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली के किराएदारों द्वारा उठाई गईं चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मैं जहां भी जाता हूं, मुझे किराए पर रहने वाले लोग मिलते हैं और वे कहते हैं कि उन्हें अच्छे स्कूल और अस्पताल की सुविधा तो मिली हैं, लेकिन वे मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं से वंचित हैं। इस मुद्दे के समाधान का आश्वासन देते हुए केजरीवाल ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव के बाद किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी का लाभ मिले। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब आम आदमी पार्टी पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपने प्रचार अभियान को तेज कर रही है।

मिल्कीपुर में अखिलेश ने किया भाजपा की हार का दावा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने मांग की है कि मिल्कीपुर उपचुनाव निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस उच्च-स्तरीय चुनावी मुकाबले पर नजर रख रही है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख ने दावा किया कि बीजेपी मिल्कीपुर में अपनी जमीन खो चुकी है। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पीडीए के प्रतिनिधि हैं। समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। मिल्कीपुर में बड़ा उपचुनाव है। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश, देश और विदेश की मीडिया को भी वहां जाकर देखना चाहिए कि भाजपा सरकार में चुनाव कैसे होते हैं। हम सरकार से यह भी कहना चाहते हैं कि मिल्कीपुर के चुनाव पर सबकी नजर है। निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ चुनाव करायें। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनावों के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा।

दिल्ली की 70 सीटों के लिए 981 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन का मौका 17 जनवरी को समाप्त हो चुका है। नामांकन खत्म होने के बाद दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए 981 उम्मीदवारों में 1521 पर्चे भरे है। नामांकन भरने के अंतिम दिन यानी 17 जनवरी को 680 नामांकन पत्र भरे गए है। चुनाव आयोग अब 18 जनवरी को कैंडिडेट्स की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी करेगा। वहीं प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20 जनवरी तय की गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सबसे कम नामांकन कस्तूरबा नगर सीट से दाखिल हुए है। कस्तूरबा नगर में कुल छह उम्मीदवारों ने नौ नामांकन पत्र दाखिल किए है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सबसे अधिक नामांकन पत्र नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से दाखिल हुए है। बता दें कि नई दिल्ली में कुल 29 उम्मीदवारों द्वारा 40 नामांकन पत्र भरे गए है। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी चुनाव मैदान में है।

निकाय चुनाव अकेले लड़ने के लिए हैं तैयार : एनसीपी

मुंबई। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में लगातार उथल-पुथल मची हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता दिलीप वाल्से पाटिल ने शनिवार को कहा कि अगर अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं बन पाता, तो एनसीपी महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बता दें, उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाली एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें भाजपा और शिवसेना भी शामिल हैं। अहिल्यानगर जिले के शिरडी में एक सम्मेलन के दौरान वाल्से ने कहा, महायुति के सभी दल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपनी रणनीति तय करेंगे। अगर गठबंधन नहीं बन पाता, तो एनसीपी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एनसीपी ने 20 नवंबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटों में से 41 पर जीत हासिल की थी। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी एमवीए और सत्तारूढ़ महायुति के बीच पहली लड़ाई होगी।

बिहार में बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष- जाति जनगणना की मांग पर कायम रहेंगे

संविधान सिर्फ किताब नहीं, इसमें हिंदुस्तान की सोच: राहुल

पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में हैं। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए राहुल ने कहा कि हम चाहते थे कि जैसे हर जगह गंगा का पानी बहता है, वैसे ही संविधान की विचारधारा भी देश के हर व्यक्ति, हर संस्था तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली तो वह भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं।

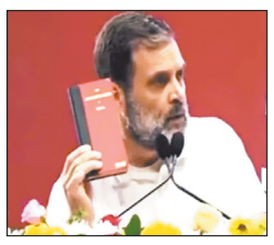

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर कड़े तेवर जारी रखते हुए राहुल ने कहा कि वह भारत के हर संस्थान से डॉ. बीआर अंबेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में कहां लिखा है कि भारत की सारी संपत्ति केवल दो या तीन लोगों के हाथों में जानी चाहिए। आज के भारत में विधायकों और सांसदों के पास कोई शक्ति नहीं है। जब मैं बीजेपी के उन सांसदों से मिलता हूं जो पिछड़े समुदाय से हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं तो वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है।

राहुल ने कहा कि जैसे हमारा संविधान इस हॉल के कोने-कोने तक पहुंच गया। वैसे ही हम संविधान को हिंदुस्तान के कोने-कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है। इस किताब में हजारों साल की सोच है। इसमें हिंदुस्तान की सोच है। इस संविधान में भगवान बुद्ध, नारायण गुरु जी, बसवन्ना जी, फुले जी, गांधी जी, अंबेडकर जी की आवाज है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ हुए अन्याय का दुख-दर्द भी है। हमारे संविधान ने इस दर्द को कम करने का काम किया है।

राहुल ने कहा कि हम जाति जनगणना की अपनी मांग पर कायम रहेंगे, यह विकास योजनाओं के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिला लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है।

अमित शाह के आंध्र दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस

- **वाईएस शर्मिला रेड्डी बोलीं- उन्हें राज्य में पैर रखने का अधिकार नहीं**

अमरावती। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के दौरे का कड़ा विरोध किया और उन पर बीआर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राज्य का दौरा करने का कोई अधिकार नहीं है। रेड्डी ने कहा कि पार्टी राज्यसभा में बीआर अंबेडकर के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी की निंदा करते हुए राज्य भर में अंबेडकर की मूर्तियों के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी।

शर्मिला रेड्डी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि डॉ. बीआर अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह को आंध्र प्रदेश में पैर रखने का कोई अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के राज्य दौरे का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम पार्टी नेतृत्व से अंबेडकर की प्रतिमाओं

पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि अमित शाह तुरंत देश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगें। उन्हें भी अविलंब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करना देश के खिलाफ देशद्रोह करने के बराबर है। विधानसभा के भरे सत्र में अंबेडकर का मजाक उड़ाकर अमित शाह ने खुद को देश का गद्दार साबित कर दिया है। इसके अलावा, बीजेपी के सहयोगी टीडीपी और जनसेना पार्टी की आलोचना करते हुए रेड्डी ने कहा कि जो लोग अमित शाह से माफी मांगने के बजाय उनकी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, वे भी देश को धोखा दे रहे हैं।

रेड्डी ने कहा कि जो लोग ऐसी देशद्रोही टिप्पणियों की निंदा नहीं करते या माफी की मांग नहीं करते, बल्कि आतिथ्य सत्कार करते हैं, वे भी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं या इस मुद्दे पर चुप रहते हैं, वे भी देश से गद्दारी के उतने ही दोषी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने टीडीपी, जन सेना सहित अपने गठबंधन सहयोगियों से अमित शाह से सार्वजनिक माफी की मांग करने का आह्वान किया है। यदि आप वास्तव में राज्य में दलित, बहुजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों का सम्मान करते हैं, तो हमारे साथ खड़े हों और अमित शाह से माफी मांगने पर जोर दें।

स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री ने बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड

कहा- आज का दिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस स्वामित्व योजना से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों लोगों को फायदा होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मप्र, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए।

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक है। यह एक बड़ी समस्या थी, लेकिन राज्य सरकारों, अधिकारियों और ग्राम पंचायत के हजारों सहयोगियों की कोशिशों से लाखों लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और आपदाएं प्रमुख हैं, लेकिन दुनिया एक और बड़ी चुनौती से जूझ रही है और वो है संपत्ति का अधिकार। कई वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक अध्ययन किया था, जिसमें कई देशों में संपत्ति के अधिकारों का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन

में पता चला कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास उनकी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज ही नहीं हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा था कि अगर गरीबी को कम करना है तो लोगों को संपत्ति का अधिकार देना बेहद जरूरी है। भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है और हमारी स्थिति भी अन्य देशों जैसी ही है। गांवों में लोगों के पास लाखों-करोड़ों रुपये की संपत्ति है, लेकिन उनके पास इसके कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में मालिकाना हक को लेकर विवाद होते हैं। कई जगहों पर ताकतवर लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व कार्ड्स बांटने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बात भी की। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, %पिछली सरकारों को इस संबंध में कुछ कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन कुछ खास नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा, कानूनी संपत्ति अधिकार मिलने के बाद लाखों लोगों ने ऋण लिया है। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपना कारोबार शुरू करने में किया है। इनमें से कई किसान हैं, जिनके लिए ये संपत्ति कार्ड वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वामित्व और भू-आधार गांवों के विकास की नींव बनेंगे।

क्या है स्वामित्व योजना?

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल, 2020 को (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर) प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। गौरतलब है कि योजना के तहत 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92 फीसदी है। वहीं, 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान

मुंबई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को और उपकप्तान शुभमन गिल को बनाया है। ये घोषणा बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने की है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। पूरी दुनिया की नजरें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के स्क्वॉड पर थी।

इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुनदार, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा को जगह मिली है।

भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद रहे।

मालूम हो कि भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इन्कार कर दिया था जिसके बाद आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का फॉर्मूला अपनाया था। चैंपियंस ट्रॉफी में आठ टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप चरण में 12 मुकाबले होंगे जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल हैं और दोनों के बीच मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सरकार बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश करेगी

नई दिल्ली। सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य मौजूदा आईटी कानून को सरल बनाना, इसे समझने योग्य बनाना और पृष्ठों की संख्या लगभग 60 प्रतिशत कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई के बजट में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। एक सूत्र के अनुसार, नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। फिलहाल, कानून के मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है और बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

क्या सच में रिलायंस की क्रिप्टो दुनिया में होगी एंट्री?

नईदिल्ली। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में ब्लॉकचेन कंपनी पॉलीगॉन लैब्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है। इसके बाद से ही 'जियोकॉइन' इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है, और यूजर्स इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स ने एक्स पर जियोकॉइन की तस्वीरें साझा की हैं, हालांकि कंपनी ने इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इंटरनेट पर जियोकॉइन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रही है। जियोकॉइन को फिलहाल एक यूटिलिटी टोकन के रूप में देखा जा सकता है। कंपनी की तरफ से जियोकॉइन को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।

कोटक महिंद्रा बैंक का नेट प्रॉफिट 10 प्रतिशत बढ़ा

नईदिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 10.22 प्रतिशत बढ़कर 4,701 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 4,265 करोड़ रुपये रहा था और जुलाई-सितंबर, 2024 तिमाही में 5,44 करोड़ रुपये रहा था। निजी क्षेत्र के बैंक का शुद्ध लाभ एकल आधार पर दिसंबर तिमाही में 3,304 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 3,005 करोड़ रुपये जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में 3,343 करोड़ रुपये रहा था। बैंक की कुल आमदनी समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 16,050 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,096 करोड़ रुपये रही। कंपनी का खर्च दिसंबर तिमाही में 10,869 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,530 करोड़ रुपये था।

खाद्य महंगाई पर नजर रखने की जरूरत : आरबीआई

नईदिल्ली। घरेलू मांग के मजबूत होने से देश की आर्थिक वृद्धि फिर से बढ़ने की ओर अग्रसर है। हालांकि, खाद्य महंगाई पर निगरानी की जरूरत है। आरबीआई ने बुलेटिन में कहा, 2025 के लिए आर्थिक दृष्टिकोण अलग-अलग देशों में भिन्न हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी है। यूरोप व जापान में मामूली सुधार हो रहा है। बुलेटिन के अनुसार, 2024-25 की दूसरी छमाही में देश की आर्थिक गतिविधियों वाले उच्च संकेतकों में तेजी आई है। यह तेजी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले वार्षिक अग्रिम अनुमानों में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि में भी दिखी है। दिसंबर में लगातार दूसरे महीने महंगाई में कमी आई है। देखा जाए तो ग्रामीण मांग में तेजी जारी है जो बेहतर कृषि संभावनाओं से समर्थित है। बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक पूंजीगत खर्च में पुनरुद्धार से प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

क्या वैश्विक बाजार में जारी रहेगी तेजी?

(गतांक से आगे...)

आकाश प्रकाश

वैश्विक वित्तीय संकट के पहले तमाम क्षेत्रों का प्रदर्शन देख लीजिए। एक दूसरे की तुलना में मूल्यांकन, निवेशकों के निवेश और डॉलर की जरूरत से ज्यादा कीमत को देखते हुए मुझे दूसरों से अलग सोचना सही लग रहा है। कोई भी संपत्ति या क्षेत्र हमेशा औरों से बेहतर प्रतिफल नहीं दे सकता।

फिर भी दूसरे पक्ष पर विचार करना हमेशा समझदारी होती है। अमेरिका में तेजी की उम्मीद क्यों लगाई जा रही है? हम कहां गलत हो सकते हैं? अमेरिका से उम्मीद लगाए विश्लेषकों और टिप्पणीकारों की रिपोर्ट पढ़कर पता लगता है कि कई लोग मूल्यांकन से चिंतित नहीं हैं क्योंकि इसका कोई समय तय नहीं होता। कई बार बाजार पारंपरिक पैमानों पर सालों महंगे रह सकते हैं। डॉट कॉम बुलबुले के दौर में केप अनुपात आज के स्तर पर पहुंचने के बाद दो साल तक शेयर बाजार चढ़ते रहे थे। उस समय बाजार ने लगातार चार साल 20 फीसदी से अधिक प्रतिफल दिया था। हो सकता है कि फिर नया बुलबुला बनने का आपका अंदेशा सही हो फिर भी 2025 में बाजार दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं। अमेरिका में अब भी केवल 2.1 फीसदी आर्थिक वृद्धि का अनुमान है मगर अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर है, जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ सकते हैं। अमेरिकी वृद्धि हर्षमिश्रित अचंभा देती जा रही है। चकित करने वाली वृद्धि, बेहतर वित्तीय स्थिति और फेड की दरों में कटौती हमेशा ही वित्तीय संपत्तियों के लिए बहुत अच्छी बात रही है। ब्याज दरों में कटौती भी हमेशा से शेयर बाजारों के लिए अच्छी रही है।

कई लोग मानते हैं कि आर्टिफिशल

इंटेलिजेंस (एआई) में भारी भरकम निवेश बरबादी या बुलबुला नहीं है। पूंजीगत व्यय में इजाफे से कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और उत्पादकता बढ़ेगी। अमेरिका में पहले ही 2 फीसदी से अधिक श्रम उत्पादकता है, जो किसी भी जी 7 देश से बहुत अधिक है। उत्पादकता अधिक होगी तो आर्थिक वृद्धि भी ज्यादा रहेगी, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा मुद्रास्फीति घटेगी। एआई के क्षेत्र में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। चार अमेरिकी कंपनियां ङ्क अल्फाबेट, मेटा, एमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट ङ्क ही 2025 में एआई पर 240 अरब डॉलर से ज्यादा पूंजी खर्च करेंगी। इस मामले में कोई उनके आसपास भी नहीं फटकता। अगर एआई इंटरनेट की तरह भारी बदलाव लाने वाली तकनीक साबित होगी तो कौन जाने कि इस निवेश का कितना अच्छा असर होगा?

अमेरिका में न तो मंदी के और न ही अर्थव्यवस्था सुस्त होने के संकेत हैं। मंदी की आहट देने वाले प्रमुख संकेतक जैसे यील्ड कर्व (बॉन्ड यील्ड और परिपक्वता में बचे समय के बीच संबंध दर्शाने वाला) या साम रूल पिछले दो महीनों में उलटी चाल चल रहे हैं। मंदी या आर्थिक सुस्ती नहीं होने पर शेयर बाजार में बिकवाली मुश्किल से ही दिखती है। फेड अब भी दरें घटाने की सोच रहा है यानी बाजार में गिरावट की स्थिति नहीं है।

मुझे लगता है कि यहां से अमेरिकी शेयरों मे पैसा यही मानकर बनाया जा सकता है कि हम डॉट कॉम बुलबुले को दोहरा रहे हैं। खुदरा धारणा के मामले में हम कहां हैं, बाजार किस तरह कुछ ही शेयरों और तकनीकी शेयरों के बल पर चढ़ रहा है, उसका मूल्यांकन दूसरों के मुकाबले कैसा है, यह सब देखकर तो यही कहा जाएगा कि बाजार बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। यह सब देखकर अमेरिका से बाहर निवेश करना ही ठीक लग रहा है चाहे निवेश समितियों को समझाना कितना ही मुश्किल क्यों न हो। आप यह सोचकर अमेरिकी बाजार में निवेश बनाए रख सकते हैं कि गिरावट से ऐन पहले आप बाजार से निकल जाएंगे। मगर हममें से ज्यादातर लोगों मे इतनी फुर्ती नहीं है। इसलिए शेयर खरीदिए मगर खबरदार रहकर।

अरुण साव का कांग्रेस पर अटैकः भय भ्रम और भ्रष्टाचार कांग्रेस के राजनीति की तीन नीतियांः अरुण साव

एक साथ होंगे पंचायत और ननि चुनाव

रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया. पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़े और इस योजना के हितग्राहियों को कार्ड का वितरण किया. ऊर्जाधानी कोरबा में भी इस योजना के तहत स्वामित्व कार्ड लोगों को बाटे गए. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने हिस्सा लिया. इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साव ने कहा कि भय, भ्रम और भ्रष्टाचार यह कांग्रेस के राजनीति की तीन नीतियां हैं. लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने संविधान की किताब हाथ में लेकर खूब भ्रम फैलाया और अब भी वह ओबीसी आरक्षण को लेकर यही कर रहे हैं.

कांग्रेस पर अरुण साव का हमलाः कांग्रेस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीधा हमला किया. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि जहां उनके गठबंधन की सरकार है, उस झारखंड राज्य में ओबीसी आरक्षण शून्य क्यों किया गया. कांग्रेस ने पहले भी संविधान की किताब हाथ में लेकर भ्रम फैलाया था. लेकिन वह सिर्फ किताब को हाथ में लेकर घूमते हैं, यह सिर्फ पढ़ने के लिए है. समझने के लिए नहीं है.हमने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण लागू किया है. अन्य राज्यों में भी इसी व्यवस्था के तहत चुनाव हुए हैं. फिर चाहे वह बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश हो. हमने सभी राज्यों का अध्ययन किया है. इस स्टडी के बाद हमने आरक्षण लागू किया है.

अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में जो नियम हमने बनाये हैं. वह अन्य राज्यों से ओबीसी के पक्ष में अधिक लाभकारी हैं. कांग्रेसियों ने झारखंड में ओबीसी आरक्षण के लिए कमेटी का गठन किया था. कमेटी का सिर्फ गठन किया, इसकी रिपोर्ट नहीं आई और वहां ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया.- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

:=डिप्टी सीएम अरुण साव ने कोरबा में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में एक साथ होंगे. सरकार की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई. हमारा अंतिम काम था पंचायत का आरक्षण तय कर इसकी सूची निर्वाचन आयोग को सौंपना, यह जिम्मेदारी भी पूरी कर ली है. कल ही राज्य के निर्वाचन आयोग ने एक बैठक ली थी. जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. तिथि की घोषणा अब कभी भी हो सकती है.पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव जब अलग-अलग होते थे. तब लगभग 80 दिन का समय लग जाता था. अधिकारी और कर्मचारी 80 दिन तक चुनाव में ही फंसे रहते थे. काफी काम प्रभावित होते थे. श्रम और संसाधनों की बर्बादी होती थी. अब जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो इसमें मुश्किल से 35 से 40 दिन का समय लगेगा. श्रम की बचत होगी. दोनों चुनाव एक साथ होंगे.- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

स्वामित्व योजना से लोगों को फायदाः स्वामित्व योजना कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना है. जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को शामिल किया गया है. कोरबा जिले में 533 गांव को पहले चरण में इस योजना के तहत शामिल किया गया है. गांव का ड्रोन और डिजिटल सर्वे किया गया. इस योजना के तहत फिलहाल 133 गांव के 8354 हितग्राहियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया गया है. कलेक्ट्रेट के सभागार में मौजूद अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों की मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया. जिन्होंने योजना की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू की है।

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिला भूमि का मालिकाना अधिकारः चौधरी

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जुड़कर स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जिले के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपकर शुभकामनाएं दीं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर के 50 हजार गांवों के 65 लाख हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे वर्षों से अपने घरों में निवास कर रहे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। अब वे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और जमीन संबंधी विवादों का भी समाधान होगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। सरकार बनते ही किसानों को बोनस राशि उनके खातों में स्थानांतरित की गई। साथ ही रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम यात्रा का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सर्वे प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कोई भी जरूरतमंद छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं को शक्ति वंदन योजना के तहत 25 हजार तक का पेपरलेस लोन देने बैंकों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने आगामी बजट में सरगुजा जिले के लिए अधिक से अधिक विकास योजनाओं को शामिल करने की बात कही।गौरतलब है कि स्वामित्व योजना के तहत जिले के 06 तहसीलों के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरण किया गया जिसमें तहसील अंबिकापुर में 283, तहसील उदयपुर में 50, तहसील लखनपुर में 40, तहसील सीतापुर में 21, तहसील बतौली में 14, तहसील लुण्ड्रा में 20, तहसील दरिमा में 43 अधिकार अभिलेख का वितरण शामिल है। इस अवसर पर अम्बिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

भाजपा शहर जिला ने किया नव प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव का अभिनन्दन

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने जगदलपुर विधायक किरण सिंहदेव को पुनः भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा रायपुर शहर जिला के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में रायपुर शहर जिला के सभी पदाधिकारियों एवं सभी 20 मंडलों के अध्यक्षों सहित किरण सिंहदेव के देवेंद्र नगर स्थित निज निवास पर पहुंचकर बधाई प्रेषित की रमेश सिंह ठाकुर ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया एवं भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना कर अभिवादन किया एवं साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए उन्हें नैवेद्य खिला कर मुंह मीठा करवाया, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के निवास पर सुबह से ही भाजपा पदाधिकारियों का हुजूम जमा था उन्हें बधाई प्रेषित करने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे आज दोपहर भाजपा रायपुर शहर जिला के सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके निवास पहुंचे थे साथ ही सभी मोर्चा के प्रमुख जैसे महिला मोर्चा सीमा संतोष साहू के नेतृत्व में जिले की महिला नेत्रियों ने भी प्रदेश अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष को बधाई प्रेषित की और युवामोर्चा के राहुल राव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के निवास के बाहर जमकर आतिशबाजी की और मिठाई वितरित की ।इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंहदेव के साथ कार्य करने का लंबा अनुभव है उनकी सरलता कार्यकर्ताओं में गहरा प्रभाव छोड़ती है उनके नेतृत्व में प्रदेश भाजपा ने उत्तरोत्तर प्रगति कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हम आशान्वित है कि भविष्य में उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भाजपा और भी निखरेगी और नए आयामों को प्राप्त कर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के नेतृत्व में रायपुर शहर जिला भाजपा को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने तैयार हैं। आज नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव को उनके निजनिवास पर बधाई प्रेषित करने जिला अध्यक्ष के साथ विशेष रूप से महामंत्री सत्यम दुवा , राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी, अकबर अली ,श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती , गोपी साहू आदि उपस्थित थे।

व्यक्ति केंद्रित चुनावी घोषणाओं से टूट रहे परिवारः मारोठिया

रायपुर। समृद्ध भारत से ही दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार हो सकेगी। विकसित भारत में हर परिवार खुशहाल और समझदार बने तभी असली विकास साबित होगा। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया में व्यक्ति को प्रभावित करने चुनावी घोषणाएं की जाती हैं, जिससे परिवार में बिखराव आते जा रहे हैं, जबकि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यह बातें वृंदावन हॉल सिविल लाइन में आयोजित विकसित भारत- सपना, योजना और वास्तविकता पर संवाद में वक्ताओं ने कही। इस कार्यक्रम का आयोजन साधना फाउंडेशन और आचार्य सरयूकांत झा स्मृति संस्थान ने विकसित भारत संवाद श्रृंखला के अंतर्गत किया। इसमें मध्यस्थ दर्शन दिल्ली के अध्येता सोमदेव त्यागी ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात् जिस आज़ादी का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वह पूरी नहीं हो रही है। तब हमारे देश में परिवार संयुक्त होते थे, साथ मिलकर सहयोग और मूल्यों के साथ लोगों का जीवन होता था। आधुनिक भारत में चुनावी प्रक्रिया खर्चीली हो गई है, राजनीतिक दल धन और प्रचार तंत्र से चुनावी जीतने को प्राथमिकता देते हैं, हर घोषणा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए होती है। हर मतदाता के लिए अलग घोषणा होने से परिवार का महत्व समाप्त होने लगा है।

समायोजन की मांग लेकर महिला शिक्षकों ने घेरा वित्त मंत्री का बंगला

रायपुर । राजधानी में शनिवार को सहायक शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ गया। बड़ी संख्या में महिला शिक्षकों ने सुबह होते ही सड़कों पर उतरकर समायोजन की मांग उठाई। शिक्षकों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले तक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की।

शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही महिला शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी समायोजन की मांग पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से सर्दी के इस कड़कड़ाते मौसम में अपने परिवार और बच्चों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। शनिवार को वित्त मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि उनके भविष्य को लेकर सरकार की उदासीनता बेहद निराशाजनक है।

कांग्रेस ने दिया समर्थनः सहायक शिक्षकों के इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षकों के मंच पर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। बघेल ने कहा था कि यह पहली सरकार है, जो पहले दी गई नौकरी को छीनने पर आमादा है। कांग्रेस ने शिक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से तुरंत समाधान की अपील की है।

शिक्षकों की मांगें: नौकरी को सुरक्षित रखने और समायोजन की गारंटी। सरकार से शिक्षकों की समस्याओं का जल्द समाधान। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान।

सहायक शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वित्त मंत्री के बंगले के बाहर डटे शिक्षकों ने कहा कि सरकार को अब जल्द से जल्द उनकी समस्याओं पर विचार करना होगा, अन्यथा प्रदर्शन और तेज किया जाएगा।सहायक शिक्षकों का आंदोलन प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

भ्रष्टाचार के कारण 15 दिन से जाम लग रहाः बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस के लिये नहीं भ्रष्टाचार करने की नीति पर काम कर रही है। राजधानी की मोवा ओवरब्रिज और बीजापुर में घटिया सड़क निर्माण मामले में कुछ अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही लीपापोती के लिये तथा बड़ी मछलियों पर से ध्यान हटाने के लिये की गयी कार्यवाही है। कुछ लोगो पर कार्यवाही करके सरकार ने मान लिया की गड़बड़ियां हुई है जो घोटाले के जिम्मेदार पीडब्लूडी मंत्री उपमुख्यमंत्री अरूण साव पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? बीजापुर में 120 करोड़ की 54.40 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी थी, जिससे बिना पूरा काम हुये सिर्फ गिट्टी बिछाने का के बाद 90 प्रतिशत से अधिक लगभग 100 करोड़ का भुगतान हो भी गया। इतना बड़ा भुगतान बिना शीर्ष अधिकारियों तथा विभागीय मंत्री की संलिप्तता के संभव नहीं है। बिना मंत्री की सहमति से 100 करोड़ का भुगतान बिना काम किये हो नहीं सकता। इस मामले में भ्रष्टाचार को उजागर करने पर एक युवा पत्रकार की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया गया था। सरकार ने ठेकेदार की जो टेन्डर निरस्त किया उसके आदेश में भी यह नहीं लिखा कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है।

सरकार बीएड शिक्षकों का तत्काल समायोजन करेः शुक्ला

रायपुर। मंत्री ओपी चौधरी के निवास पर अपनी व्यथा सुनाने गये बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त शिक्षकों के साथ किये गये दुर्व्यवहार और अमानवीय बर्ताव की कांग्रेस ने कड़ी निंदा किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक कोई अपराधी नहीं है। वे सरकार की अनिर्णय वाली स्थिति का शिकार है। साय सरकार उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग में समान वेतन पर समायोजन करने के बजाये उनको पुलिस से प्रताड़ित कराया जाना अनुचित है। कांग्रेस मांग करती है कि बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों को तत्काल नौकरी पर बहाल किया जाये, नये जगह समायोजन किया जाये। ओपी चौधरी जब विपक्ष में थे तब रोज शैक्षणिक संस्थानों कोचिंग संस्थानों में जाकर युवाओं के रोजगार के लिये लक्षेदार बाते करते थे। आज जब सत्ता में आ गये है तो उनको युवाओं से मिलने की फुर्सत नहीं है। उनके घर न्याय मांगने पहुंची महिला शिक्षकों उनके दुधमुंहे बच्चों को घंटो तक अवैधानिक रूप से बंधक बनवाया गया। उनको संगीन धाराओं में फंसाने की धमकियां दिलवाया गया। सत्ता में आने के बाद भाजपाई सत्ताधीशों की मानवीय संवेदना नष्ट हो गयी है।

पेंशनरों ने निवनियुक्ति भाजपा अध्यक्ष को दी बधाई

रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को किरणदेव सिंह से उनके निवास पर देवेन्द्रनगर रायपुर में मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर गुलदस्ता-शाल भेंट कर शुभकामनाएं व्यक्त कर बधाई दिया।

इस दौरान उनसे मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने और मोदी के गारंटी के तहत केन्द्र के समान जुलाई 24 से बकाया 3 प्रतिशत महंगाई राहत की राशि एरियर सहित दिलाने में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को दोनों मांगों पर जरूरी कार्यवाही करने का भरोसा दिया। प्रतिनिधि मंडल में पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी,कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, प्रदेश संयोजक अनिल पाठक, रायपुर जिला अध्यक्ष आर जी बोहरे तथा पुलिस प्रकोष्ठ प्रमुख नरसिंग राम आदि शामिल थे।

मृत एएसआई का पुत्र अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के निरस्त होने के बाद उनके विधिक वारिस अनुकम्पा नियुक्ति और अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने का हकदार बताया है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का गृह विभाग के सचिव को आदेश दिया है. हाई कोर्ट का यह फैसला विक्की भारती की याचिका पर है. दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ बूंदराम भारती को सेवाकाल के दौरान 18 अगस्त 2017 को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था. उक्त आदेश के विरूद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी. इसी दौरान 9 अक्टूबर 2018 को उनकी मृत्यु हो गई.मृत्यु के 21 दिन गृह विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर बूंदराम भारती का अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश निरस्त कर सेवा में बहाल करने का आदेश किया. बूंदराम भारती की मृत्यु होने की वजह से उनके पुत्र विक्की भारती ने विभाग के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत किया.इस पर गृह विभाग ने मृत्यु के समय बूंदराम भारती पुलिस विभाग की सेवा में ना होकर अनिवार्य सेवानिवृत्त होने का तर्क देते हुए विक्की भारती की अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया.

महिला आयोग का फैसला, हर महीने 3 हजार रुपए देगा पति

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज रायपुर कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की. आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 302 सुनवाई हुई. एक प्रकरण के दौरान आवेदिका ने बताया कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरा विवाह कर लिया है, जिससे उनकी एक बच्ची भी है. अनावेदक द्वारा आवेदिका और बच्चों को काई भी भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है. इस मामले में महिला आयोग ने कहा, यह एक अपराधिक प्रकरण है और सजा पाने का पर्याप्त आधार है. आयोग की समझाइश पर पति ने प्रति माह 3 हजार रुपए और ससुर ने 1 एकड़ जमीन आवेदिका और उसके बच्चों को दिए जाने की सहमति दी.एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि आवेदिका के पति ने किए गए कार्यों का बकाया भुगतान नहीं किया है. अनावेदिका के कार्यकाल के दौरान 70 हजार रुपए का भुगतान नहीं किया गया है. इस मामले में पूर्व में कार्यरत अधिकारी और उनके स्वयं के कार्यकाल का बकाया आवेदिका पक्ष को मिला और 28 हजार का भुगतान का बिल ट्रेजरी में जमा हुआ।

छत्तीसगढ़ में स्वामित्व कार्ड का वितरण

छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में हुआ स्वामित्व कार्डों का वितरण

रायपुर/ बलरामपुर/ दुर्ग/ राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रदेश के कई जिलों में इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड बांटा गया. बलरामपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में इसके तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया. पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर इस योजना का शुभारंभ किया. उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया.

बलरामपुर में हुआ खास आयोजनः बलरामपुर के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में स्वामित्व योनजा के तहत लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए. मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और जिले के कलेक्टर इस कार्यक्रम में शामिल हुए. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के पांच विकासखंड के कुल 757 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है. जिसमें विकासखण्ड बलरामपुर में 76 अधिकार पत्र, रामानुजगंज में 184, वॉड्रफनगर में 122 ,राजपुर में155 और कुसमी में 220 अधिकार पत्र हितग्राहियों को बांटे गए हैं. इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से भू-अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करने का काम किया जा रहा है.

इस योजना के माध्यम से

आमजन को इसका लाभ मिलने वाला है उनके घर के जमीनों का रिकॉर्ड उसके पास रहेगा उस रिकॉर्ड के आधार पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं. लोगों को पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

दुर्ग में स्वामित्व योजना कार्ड का वितरणः दुर्ग में स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया. जिले के बीआईटी कॉलेज ग्राउंड में इस योजना के तहत कार्ड वितरित किए गए. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े थे. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी जुड़े. उन्होंने लोगों को स्वामित्व कार्ड बांटे. इसके तहत लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इस कार्ड से लोगों को संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी अधिकार मिला है. जिसके तहत आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.

इस योजना के लागू होने से गांव देहात के लोगों को काफी मदद मिलेगी. स्वामित्व योजना के तहत कार्ड मिलने से लोग अपनी जमीन का फायदा उठा सकेंगे. ग्रामीणों को बैंक लोन प्राप्त करने, संपत्ति का लेन-देन करने और कानूनी रूप से अपने अधिकार सिद्ध करने में कठिनाई नहीं होगी-विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

राजनांदगांव के लोगों को मिली खुशियांः राजनांदगांव में भी स्वामित्व योजना को लेकर कार्यक्रम किया गया. यहां के जिला पंचायत कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन हुआ. पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े. इसमें छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए. इस योजना के तहत राजनांदगांव के कई ग्रामीण हितग्राहियों को फायदा मिला. पूरे देश में 5 वर्ष पूर्व अप्रैल 2020 में इस योजना का शुभारंभ किया गया. अब तक इस योजना से दो करोड़ से ज्यादा लोगों को मदद पहुंची है.

भौतिक सत्यापन में मिली गड़बड़ी, 14 खरीदी प्रभारियों को नोटिस

बिलासपुर। भौतिक सत्यापन में मिली गड़बड़ी के आधार पर 14 धान खरीदी केंद्रों के खरीदी प्रभारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उपायुक्त सहकारिता ने आज नोटिस इश्यू किए हैं। उनसे रविवार 19 जनवरी को शाम 4 बजे तक जवाब तलब किया गया है। खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर धान खरीदी केंद्र एरमशाही, जयरामनगर, रिसदा, सारधा,बोड़सरा, सोन,पोंड गनियारी, टांडा, कुकदा, पोड़ी, जाँजी, मस्तूरी और कौड़ियां के समिति प्रबंधक/ खरीदी प्रभारी को नोटिस आज जारी किया गया है। उन्हें गड़बड़ी की जानकारी देकर इस संबंध में सबूत के साथ स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

खाद्य अधिकारी ने एक अन्य जानकारी में बताया कि धान खरीदी केंद्र घुटकु का भौतिक सत्यापन किया गया। ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर 41621 धान की कट्टी है जबकि प्वाइंटर के माध्यम से गिनती उपरांत 40621 कट्टी मौके पर है।

अतः समिति में 1000 कट्टी धान कम पाया गया। जिसका मौके में पंचनामा बनाया गया। वहां के खरीदी प्रभारी को भी नोटिस दिया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.